नई दिल्ली
26
जून, 2026
शुक्रवार
मूल्य : 01 रुपए
पृष्ठ : 08
वर्ष : 14
अंक : 86

अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इन्साफ की डगर पर

टाइम्स ऑफ़ पीडिया

RNI No. DELMUL/2012/47011

www.timesofpedia.com

Email : timesofpedia@gmail.com

ब्रॉड भी हुए वैभव के मुरीद, बोले उससे संभलकर रहे इंग्लैंड के गेंदबाज 07

संक्षिप्त वार्ता

लॉरेंस बिश्नोई-अनिल पंडित गिरोह के दो शूटर स्पेशल सेल के साथ मुठभेड़ में घायल

नई दिल्ली, वेब वार्ता

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल (सीआईए शाखा) के साथ पश्चिमी दिल्ली में हुई मुठभेड़ में लॉरेंस बिश्नोई और अनिल पंडित गिरोह के दो शूटर घायल हो गए। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार, आरोपियों की पहचान हकीकत और सागर के रूप में हुई है। दोनों किसी वारदात को अंजाम देने पहुंच रहे थे। पुलिस टीम को देखकर उन्होंने कथित तौर पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। इस दौरान दोनों के पैर में गोली लगने से घायल हो गये।

प्रदेश के लाखों कर्मचारी को राहत, फिर शुरू होगी पदोन्नति की प्रक्रिया

वेब वार्ता, भोपाल

प्रदेश में पिछले 10 साल से पदोन्नति की राह देख रहे 3 लाख से ज्यादा अधिकारी एवं कर्मचारियों को फिर पदोन्नति की उम्मीद जगी है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। जिसके तहत 1 जुलाई से विभाग पदोन्नति दे सकते हैं। इससे पहले सरकार की ओर से पदोन्नति नियम 2025 को लेकर न्यायालय में कैबिनेट दायर की जाएगी।

दरअसल, मप्र हाईकोर्ट में पदोन्नति नियम 2025 को लेकर लगाई गईं याचिकाओं पर सुनवाई कर रही बैंच के न्यायाधीशों का तबादला हो गया है। जिसमें हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा का दिल्ली तबादला हो गया है। जबकि जस्टिस विनय सर्राफ का इंदौर तबादला हो गया है। ऐसे में बैंच ने पदोन्नति मामले में आखिरी सुनवाई फरवरी 2026 में की थी। बैंच ने सुनवाई के बाद फैसला रख लिया था। बताया गया कि बैंच के दोनों जजों का तबादला होने के बाद सरकार पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू कर सकती है।

अमोनिया गैस रिसाव: एक और मजदूर ने तोड़ा दम

वेब वार्ता, चेन्नई

तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में स्थित एक निजी सीफूड प्रोसेसिंग (समुद्री खाद्य प्रसंस्करण) यूनिट में हुए अमोनिया गैस रिसाव हादसे का कहर थमता नजर नहीं आ रहा है। इस दर्दनाक दुर्घटना में एक और मजदूर की मौत हो जाने के बाद जान गंवाने वालों की कुल संख्या बढ़कर 11 हो गई है। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार, हादसे से प्रभावित हुए कुल 83 मजदूरों में से 67 श्रमिक अभी भी चेन्नई और तिरुवल्लूर के विभिन्न अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उपचाराधीन मरीजों में डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में 64 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। इनमें से 16 मरीजों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और वे वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं, जबकि 21 मरीजों को नाक के जरिए (नेजल) ऑक्सीजन दी जा रही है।

भारत आ रहे 30 जहाजों ने किया होर्मुज पार, आधे में एलपीजी-एलएनजी लदा

मिडिल ईस्ट से भारत आ रहे 30 जहाजों ने होर्मुज पार कर लिया है, जबकि 26 जहाज इस समुद्री मार्ग से गुजरने के लिए अभी भी इंतजार में हैं, शिपिंग मंत्रालय के सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है।

वेब वार्ता, नई दिल्ली

अधिकारियों के मुताबिक जलडमरूमध्य पार कर चुके 30 जहाजों में से करीब आधे जहाजों पर एलपीजी और एलएनजी लदा हुआ था। इसके अलावा, आठ जहाजों पर थोक माल मौजूद था और सात कच्चे तेल के टैंकर थे।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि 1 मार्च से 17 जून के बीच 19 जहाजों ने इस समुद्री मार्ग को पार किया था। वहीं ईरान और अमेरिका के बीच डीज होने के बाद से 11 जहाजों ने जलडमरूमध्य को सुरक्षित रूप से पार किया है। भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच चुके या उनकी ओर बढ़ रहे इन 30 जहाजों में से 17 विदेशी झंडे वाले जहाज हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पांच जहाज मार्शल आइलैंड्स के झंडे तले चल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक होर्मुज जलडमरूमध्य के पश्चिम फारस की खाड़ी में अभी भी भारतीय हितों से जुड़े 26 जहाज मौजूद हैं। इनमें भारतीय झंडे वाले और भारत आ रहे विदेशी झंडे वाले, दोनों तरह के जहाज हैं। इन 26 जहाजों में से तीन में ऊर्जा उत्पाद, 10 में उर्वरक और बाकी 13 जहाजों में अन्य सामान लदा है।

पश्चिम फारस की खाड़ी में अभी भी 26 जहाज मौजूद कर रहे बारी का इंतजार

रिपोर्ट के मुताबिक होर्मुज एक बेहद अहम अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है, जहां से दुनिया भर की कुल ऊर्जा आपूर्ति का लगभग पांचवां हिस्सा गुजरता है। भारत के लिए यह मार्ग विशेष रूप से मायने रखता है, क्योंकि एलएनजी और एलपीजी की खरीद के लिए उसके प्रमुख व्यापारिक भागीदार खाड़ी देशों में ही स्थित हैं।

अधिकारों और कर्तव्यों का प्रतीक

हमारा संविधान 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं

वेब वार्ता, नई दिल्ली

पीएम नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस के अवसर पर कहा कि यह दिन आज हमें उस काले दौर की याद दिलाता है, जब भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला गया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम ऐसे भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों के प्रति सदैव समर्पित रहे। पीएम मोदी ने गुरुवार को एक्स पर लिखा कि आज हम उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने भारत के इतिहास के सबसे काले दौर में से एक, यानी आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती से रक्षा की।

उन्होंने लिखा- आपातकाल हमारे संविधान पर सीधा हमला था। इस दौरान नागरिक स्वतंत्रताएं छीन ली गई थीं, अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगा दी गइ थी, राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों और समाज सेवकों को गिरफ्तार किया गया व उन संस्थाओं पर हमला किया गया, जो हमारे लोकतंत्र की नींव हैं। साथ ही उस दौर ने अनगिनत नागरिकों के असाधारण साहस को भी दिखाया, जिन्होंने चुप रहने से इनकार कर दिया और हमारे संविधान में निहित आदर्शों को बनाए रखा। पीएम ने एक्स पोस्ट में कहा कि हम सभी के लिए, हमारा संविधान 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं, अधिकारों और कर्तव्यों का प्रतीक है।

हम संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। अपने संविधान की भावना से प्रेरित होकर हम एक ऐसा भारत बनाएंगे, जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहे। एक अन्य पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि संविधान हत्या दिवस आज हमें उस काले दौर की याद दिला रहा है, जब भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला गया था। यह हमें लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहने को प्रेरित करता है। आपातकाल का विरोध करने वाली सभी विभूतियों को सादर नमन।

इसके साथ ही पीएम मोदी ने संस्कृत सुभाषितम् शेयर करते हुए लिखा- स्वातन्त्र्यात सुखमाप्नोति स्वातन्त्र्याल्लभते परम्। स्वातन्त्र्यान्निर्वृत्तिं गच्छेत् स्वातन्त्र्यात परमं पदम्। इसमें कहा गया है, स्वतंत्रता से ही मनुष्य सुख प्राप्त करता है, स्वतंत्रता से ही वह सर्वोच्च उपलब्धि पाता है। स्वतंत्रता से ही वह शांत अवस्था को प्राप्त होता है और स्वतंत्रता के जरिए ही वह परम पद को प्राप्त करता है।

सतपुड़ा के कुकरु में दो दिन रहेंगे सीएम मोहन यादव

भोपाल। बैतूल जिले के सतपुड़ा अंचल में बसे हिल स्टेशन कुकरु को प्रदेश के पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाने की दिशा में सरकार ने

कदम तेज कर दिए हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 27 और 28 जून को दो दिवसीय प्रवास पर कुकरु पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री का यह दौरा केवल प्रशासनिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे क्षेत्र के विकास और पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री यहां रात्रि चौपाल लगाएंगे, किसी ग्रामीण परिवार के घर भोजन करेंगे और दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का श्रवण ग्रामीणों एवं कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान कुकरु को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की जा सकती हैं।

ईरान बहुत बड़ी रियायतें दे रहा, मेरी हर बात मान रहा: राष्ट्रपति ट्रंप

वेब वार्ता, वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया कि ईरान अमेरिका के साथ चल रही बातचीत में बहुत बड़ी रियायतें दे रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि कूटनीति आगे बढ़ रही है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी कि यदि आवश्यक हुआ तो अमेरिका सुरक्षा बल का उपयोग करने के लिए तैयार है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में नाटो के महासचिव मार्क रूटे के साथ अपनी बैठकों से पहले और बाद में मीडिया से बात करते हुए तेहरान के साथ कूटनीति पर सकारात्मक रुख व्यक्त किया। हालांकि, उन्होंने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि सैन्य विकल्प अभी भी मेज पर है। रिपब्लिकन सांसदों के साथ दोपहर के भोजन से पहले ट्रंप ने कहा, जंग बहुत अच्छी चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं, हम जीत रहे हैं। ईरान बहुत बड़ी रियायतें दे रहा है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन यह बहुत दमदार रहा है और यह बहुत अच्छा चल रहा है। अपनी बैठक के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि तेहरान अमेरिका की मांगों को पूरा कर रहा है। उन्होंने कहा, ईरान बहुत अच्छा बर्ताव कर रहा है। वे मेरी हर बात मान रहे हैं और उन्हें मानना ही होगा। नहीं तो, हम बस वापस जाकर वही करेंगे जो हमें करना है।

मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा

ट्रंप ने भविष्य में किसी भी ऐसे समझौते को भी स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया जो ईरान को होर्मुज स्ट्रेट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग पर शुल्क लगाने की अनुमति देगा। उन्होंने दृढ़ता से कहा, यह मुझे मंजूर नहीं होगा। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा चोकपॉइंट्स में से एक है, और इस पर ईरान का नियंत्रण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए गंभीर निहितार्थ रखता है।

राम मंदिर ट्रस्ट दान विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार

याचिकाकर्ताओं को अगले सप्ताह दोबारा मेंशन करने का दिया निर्देश

नई दिल्ली, वेब वार्ता

सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कथित वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने याचिकाकताओं को इस मामले को अगले सप्ताह यानी सोमवार, 29 जून को अदालत के समक्ष दोबारा मेंशन (उल्लेख) करने का निर्देश दिया है। यह याचिका दो वकीलों, अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव द्वारा दायर की गई है, जिसमें ट्रस्ट के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं।

याचिकाकताओं ने अपनी अर्जी में ट्रस्ट के कोष में बड़े पैमाने पर हुए कथित गबन और वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों की गहन जांच की गुहार लगाई है। याचिका में मांग की गई है कि इस मामले में सबसे पहले संबंधित आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की जाए। इसके बाद पूरे मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जाना बेहद जरूरी है।

महत्वपूर्ण साक्ष्यों को नष्ट करने की जताई आशंका

याचिका में महत्वपूर्ण साक्ष्यों को नष्ट किए जाने की आशंका भी जताई गई है, जिसके चलते याचिकाकताओं ने अदालत से उत्तर प्रदेश सरकार और राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बैंक खातों, दान रजिस्टर, ऑडिट रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज जैसे सभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश देने की मांग की है। इसके अतिरिक्त, भविष्य में ऐसी शिकायतों को रोकने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए फंड व संपत्तियों की निगरानी हेतु एक मजबूत स्वतंत्र ऑडिट व्यवस्था विकसित करने का भी सुझाव दिया गया है।

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर दो विमान आमने-सामने आए, बड़ा हादसा टला

अहमदाबाद। अहमदाबाद हवाई अड्डे परन पार्किंग बे की ओर जाते समय एअर इंडिया का एक विमान गलत दिशा में मुड़ गया, जिससे वह इंडिगो के एक विमान के सामने आ गया। हालांकि दोनों विमान एक-दूसरे से सुरक्षित दूरी पर रुक गए। सूत्रों ने बताया कि मुंबई जा

रहा इंडिगो का विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था, तभी एअर इंडिया का विमान गलत दिशा में मुड़ गया और वह उसी टैक्सीवे पर आ गया, जिस पर इंडिगो का विमान खड़ा था। सूत्रों के मुताबिक टैक्सीवे पर दोनों विमान समय रहते एक-दूसरे से करीब 200 मीटर की सुरक्षित दूरी पर रुक गए। एअर इंडिया ने एक बयान में कहा कि हमें उस घटना की जानकारी है, जिसमें 24 जून को मुंबई से अहमदाबाद जाने वाली हमारी एआई 2493 उड़ान लैंडिंग के बाद ह्यपार्किंग बेह्न की तरफ जाते समय अनजाने में गलत रास्ते पर मुड़ गई थी। विमानन कंपनी ने कहा कि विमान में सवार यात्री और चालक दल के सदस्य पूरी तरह सुरक्षित हैं। उसने बताया कि बाद में विमान को सुरक्षित रूप से पार्किंग बे में ले जाया गया।

नगरीय चुनाव से पहले भाजपा का बड़ा दांव

एल्डरमैन बनेंगे चुनावी सेनापति, साधे जाएंगे नाराज नेता

वेब वार्ता, भोपाल। मध्यप्रदेश भाजपा ने अगले साल होने वाले नगरीय निकाय चुनावों की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। प्रदेश कार्यसमिति और मोर्चों की नियुक्तियों के बाद अब पार्टी की नजर प्रदेश के 244 नगरीय निकायों में होने वाली एल्डरमैन नियुक्तियों पर टिक गई है। संगठन के भीतर इसे महज प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के बीच इस विषय पर कई दौर की चर्चा हो चुकी है। अगले एक सप्ताह के भीतर प्रदेश के शेष नगरीय निकायों में एल्डरमैनों की नियुक्ति की घोषणा होने की संभावना है।

भाजपा के लिए यह नियुक्तियां कई राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने का माध्यम बन सकती हैं। हाल ही में प्रदेश संगठन, मोर्चों और प्रकोष्ठों में हुई नियुक्तियों में कई वरिष्ठ नेता और पुराने कार्यकर्ता जगह नहीं बना पाए थे। पार्टी अब एल्डरमैन पदों के जरिए ऐसे नेताओं को सम्मानजनक जिम्मेदारी देकर संगठन में संभावित असंतोष कम करना चाहती है। विशेष रूप से विधानसभा और लोकसभा चुनावों में सक्रिय भूमिका निभाने वाले कार्यकताओं को प्राथमिकता मिलने की चर्चा है। इससे पार्टी एक साथ संगठनात्मक संतुलन और चुनावी सक्रियता दोनों बनाए रखने की कोशिश कर रही है।

चुनावी नेटवर्क तैयार करने की रणनीति

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा इन नियुक्तियों के जरिए स्थानीय स्तर पर अपना चुनावी नेटवर्क मजबूत करना चाहती है। एल्डरमैन परिषद की बैठकों में भाग लेकर स्थानीय मुद्दों से सीधे जुड़ते हैं और संगठन तथा परिषद के बीच समन्वय की भूमिका निभाते हैं। मतदान का अधिकार नहीं होने के बावजूद स्थानीय राजनीति में उनकी पकड़ प्रभावशाली मानी जाती है। यही कारण है कि भाजपा इन्हें आगामी नगरीय निकाय चुनावों के लिए ग्राउंड मैनेजर के रूप में तैयार कर रही है।

प्रदेश के 16 नगर निगमों में 12-12 एल्डरमैन नियुक्त किए जाएंगे। इनमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, रीवा, सतना, सिंगरौली, मुरैना, छिंदवाड़ा, देवास, कटनी, रतलाम, खंडवा और बुरहानपुर शामिल हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इन्हीं नगर निगमों को लेकर है, क्योंकि बड़े शहरों में संगठन और जनप्रतिनिधियों के बीच संतुलन बनाना पार्टी के लिए चुनौती माना जाता है। जिला स्तर के कोर ग्रुप संभावित नाम पहले ही प्रदेश नेतृत्व को भेज चुके हैं और अंतिम सहमति की प्रक्रिया चल रही है।

इसी बीच भाजपा नई प्रदेश कार्यसमिति की पहली बैठक भी राजधानी से बाहर आयोजित करने जा रही है। 15 और 16 जुलाई को धार्मिक एवं पर्यटन नगरी ओरछा में दो दिवसीय प्रदेश कार्यसमिति बैठक होगी। कई वर्षों बाद प्रदेश कार्यसमिति का इतना बड़ा आयोजन भोपाल से बाहर किया जा रहा है। बैठक में सांसद, विधायक, प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा प्रमुख और कार्यसमिति सदस्य शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार बैठक में आगामी नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत स्तर तक संगठन विस्तार, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार तथा बदलते राजनीतिक समीकरणों पर विस्तृत चर्चा होगी।

एनसीईआरटी की कक्षा 9 की किताब में पहली बार जुड़ा आपातकाल चैप्टर

नई दिल्ली, वेब वार्ता। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने अपने नए पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव करते हुए कक्षा 9 की सोशल साइंस की किताब में आपातकाल (1975-77) को पहली बार शामिल किया है। नई पाठ्यपुस्तक ह्यअंडरस्टैंडिंग सोसाइटी: इंडिया एंड बियॉन्डह्न में इसे भारतीय लोकतंत्र के सामने आई एक प्रमुख चुनौती के रूप में दर्ज किया गया है, जहाँ छात्रों को उस दौरान निलंबित हुए मौलिक अधिकारों

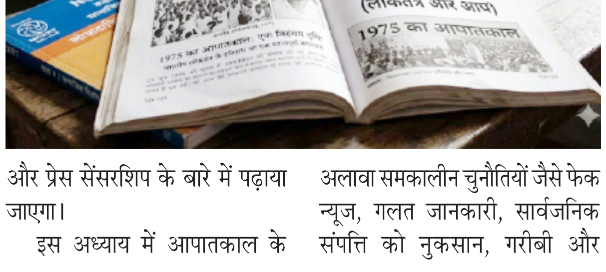

और प्रेस सेंसरशिप के बारे में पढ़ाया जाएगा।

इस अध्याय में आपातकाल के अलावा समकालीन चुनौतियों जैसे फेक न्यूज, गलत जानकारी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, गरीबी और सामाजिक भेदभाव जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। इसके साथ ही ह्यलोकतंत्र और आप नामक एक नया सेक्शन जोड़ा गया है, जिसका उद्देश्य छात्रों को एक जागरूक नागरिक के रूप में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में अपनी सक्रिय भूमिका और जिम्मेदारी को बेहतर ढंग से समझना है। संशोधित किताब में लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका को चौथा स्तंभ बताते हुए इसके महत्व को रेखांकित किया गया है। साथ ही, भारत की लोकतांत्रिक मजबूती को दर्शाने के लिए 2024 के आंकड़ों और वोटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ जमीनी स्तर के लोकतंत्र, जैसे पंचायत व्यवस्था और महिला आरक्षण जैसे विषयों को भी शामिल किया गया है, ताकि विद्यार्थी भारतीय लोकतांत्रिक परंपराओं की व्यापक समझ विकसित कर सकें।

भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों और इतिहास को गहराई से समझेंगे छात्र

संपादकीय

और कितने लाक्षागृह

यह अग्निकांड नहीं, हत्याकांड है। यह हादसा या दुर्घटना नहीं, कत्लेआम का बंदोबस्त है। यह आधुनिक दौर का लाक्षागृह कांड है। ऐसी हत्याएं यहीं नहीं रुकेंगी, क्योंकि यह हमारी व्यवस्था की निरंतर नाकामी है। नगर निगम आंख मूंद कर सोया है, निर्लिप्त है, कोई चिंता-सरोकार नहीं है। बिजली विभाग को करंट दो, क्योंकि वह सन्नाटे में बेसुध है। फायर ब्रिगेड के भीतर जान बचाने का जज्बा बुझ चुका है। ये विभाग और बड़े अधिकारी सिर्फ चाय-पानी की प्रतीक्षा में हैं। उनकी औलादें विदेश में या बेहतर व्यवस्था के संस्थानों में कम्प्यूटर पर खेल रही हैं। आग विदेश में भडकती है, धुआं वहां भी काला और दमघोंटू होता है। लाक्षागृह स्तरीय संस्थानों में भी बनाए जा सकते हैं। एक बार किसी मंत्री, मुख्यमंत्री, मेयर, सचिव, निदेशक का बच्चा ऐसे लाक्षागृह में फंसना चाहिए, लेकिन उसके दम घुटने अथवा जिंदा जल जाने की कल्पना भी हम नहीं करेंगे। लाक्षागृह लखनऊ में ही नहीं हैं। इसी महीने की शुरूआत में राजधानी दिल्ली के एक गेस्ट हाउस में अग्निकांड हो गया था। 21-22 निर्दोष, अतिथि मारे गए। राजधानी दिल्ली के विवेक विहार, पालम, द्वारिका आदि में भी कई लोग जिंदा जल कर खाक हो गए। उनकी क्षतिपूर्ति 5-10 लाख रुपए आंकी गई और अध्याय खत्म..! फिर एक और लाक्षागृह का इंतजार! देश के आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात आदि राज्यों में लाक्षागृह धू-धू कर जले हैं। कितना होश आया, व्यवस्था बदली या बुलडोजर चलाए गए? देश में और कितने ऐसे लाक्षागृह हैं, कोई नहीं बता सकता। ईश्वर भी असहाय साबित होंगे। जांच के नाम पर कुछ ढोंग किए जाते हैं, कुछ इमारतें सील की जाती हैं, छोटे कर्मचारी निलंबित कर दिए जाते हैं, बसहो गया न्याय! सरकारें मुआवजे बांटने को लालायित रहती हैं। शायद उनसे भी वोट मिलते होंगे! सरकारें अवैध, अतिक्रमण वाले, असुरक्षित, बिन अग्निशमन सिस्टम के, बड़े-बड़े निमार्णों, इमारतों, होटलों, मॉल, अस्पताल, स्कूल-कॉलेज की तरफ आंख उठा कर भी नहीं देखतीं, क्योंकि चाय-पानी मिल चुका होता है।

हमारी संपूर्ण व्यवस्था ही बेईमान, भ्रष्ट, नालायक और सुप्तावस्था में है। नतीजतन लाक्षागृह बनते जा रहे हैं। लखनऊ में भी कुछ अधिकारियों को निलंबित करने से कुछ नहीं होगा। जिनके कार्यकाल में ये लाक्षागृह बनाए गए हैं, उन्हें सरकारी सेवाओं से, तुरंत प्रभाव से, बर्खास्त कर देना चाहिए। सरकारें अदालती चुनौतियों को भी झेलें और उन्हें यथार्थ से अवगत कराएं। सरकारों को ऐसा दंडात्मक रुख अख्तियार करना पड़ेगा। लाक्षागृह में आग लगने से 2005-15 में सालाना 17,700 से अधिक मौतें हुई हैं। 2015-24 के दौरान 10,909 मौतें! अर्थात 25-30 लाक्षागृह मौतें हररोजङ्ग! कितना खौफनाक, त्रासद आंकड़ा है यह? 2024 की रपट भी सामने है, जिसके मुताबिक उस साल 5971 लाक्षागृह कांड हुए, जिनमें 5888 मौतें हुईं। क्या ऐसा देश विश्व-गुरु होने की खुशफहमी भी पालने लायक है? स्मार्ट सिटी बनाने की परियोजना ही बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि हम ऐसा ढांचा बनाने में अक्षम हैं। हम चेतना-सोच के स्तर पर स्मार्ट होने से बहुत दूर हैं। क्यों करदाताओं के करोड़ों रुपए स्मार्टफहमी के नाम पर फूंके जा रहे हैं? जिन्हें चाय-पानी की लार परेशान कर रही है, उन्हें सत्ता और प्राधिकरण के दफ्तरों से बाहर कर देना चाहिए। यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री यह काम नहीं कर सकते, तो यह काम भी देश की आक्रोशित जनता कर सकती है। यह लापरवाही, अनदेखी और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है कि 70 फीसदी से अधिक दिल्ली लाक्षागृह की आशंका, अंदेशों के साथ जी रही है। जरा दिल्ली के सदर बाजार, चांदनी चौक, करोल बाग, पहाडगंज सरीखे बाजारों में घूम कर अनुभव लें। दिल्ली की बड़ी-बड़ी इमारतों के परिसर में जाकर उनकी पुरानी, संकरी व्यवस्था को देख लें, नंगी तारों के झुंड भी जरूर देखना, तो आप एकबारगी सिहर उठेंगे। डर जाएंगे और वहां से एकदम भागना चाहेंगे, क्योंकि वे तमाम लाक्षागृह ही हैं। यह देश की राजधानी का यथार्थ है। हमारी विडंबना और दुर्भाग्य है कि कानून में लाक्षागृह कांड को अपराध अथवा हत्या नहीं, बल्कि दुर्घटना-हादसा माना गया है, नतीजतन अधिकतर आरोपित सालों से जमानत पर घूम रहे हैं। क्या वाकई ये अग्निकांड हादसे ही हैं? इस तरह की घटनाएं बार-बार हो रही हैं और हम कोई सबक नहीं ले रहे हैं। हर घटना के बाद जांच होती है, कुछ बयान जारी होते हैं, और कुछ दिनों के बाद सब कुछ भुला दिया जाता है। जरूरत इस बात की है कि ऐसे मामलों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि ये घटनाएं फिर न हों।

मादक पदार्थों का बढ़ता साम्राज्य और सिमटते सपने

किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी के सपनों, ऊर्जा और सृजनशीलता पर निर्भर करता है लेकिन जब यही युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आने लगे तो यह केवल एक सामाजिक समस्या नहीं रह जाती बल्कि राष्ट्रीय संकट का रूप धारण कर लेती है। आज भारत सहित दुनिया के अनेक देशों के सामने यही चुनौती खड़ी है। युवाओं की प्रतिभा, उनकी सोच, उनकी रचनात्मकता और उनके भविष्य पर नशे का ऐसा ग्रहण लग रहा है, जो न केवल परिवारों को बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र को भीतर से खोखला कर रहा है। इसी गंभीर चुनौती के प्रति वैश्विक जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 26 जून को ह्यअंतर्राष्ट्रीय नशा एवं मादक पदार्थ निषेध दिवसह्ल मनाया जाता है। यह दिवस केवल औपचारिक आयोजन नहीं बल्कि पूरी मानवता को चेताने का अवसर है कि यदि नशे के बढ़ते दुष्चक्र को समय रहते नहीं रोका गया तो इसके परिणाम आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतने पड़ेंगे।

भारत में नशे की समस्या अब महानगरों तक सीमित नहीं रही। यह गांवों, कस्बों, छोटे शहरों और यहां तक कि स्कूलों तथा कॉलेजों तक पहुंच चुकी है। कभी माना जाता था कि नशीले पदार्थों का सेवन केवल संपन्न वर्ग या शहरी संस्कृति की समस्या है लेकिन आज वास्तविकता इससे कहीं अधिक भयावह है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अफीम, चरस, गांजा, हेरोइन, सिंथेटिक ड्रग्स और इंजेक्शन के माध्यम से लिए जाने वाले नशीले पदार्थों का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। यह स्थिति बताती है कि नशे का नेटवर्क अब समाज की हर परत तक पहुंच चुका है। आज का युवा अनेक प्रकार के दबावों से घिरा हुआ है। प्रतिस्पर्धा, बेरोजगारी, सामाजिक अपेक्षाएं, पारिवारिक तनाव, मानसिक अवसाद, अकेलापन और त्वरित सफलता की चाह उसे भीतर से कमजोर बना रही है। ऐसे में नशे के सौदागर युवाओं की इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं। कई बार मित्रों का दबाव, आधुनिक दिखने की चाह, रोमांच की तलाश या क्षणिक सुख का आकर्षण युवाओं को नशे की ओर धकेल देता है। शुरूआत अक्सर जिज्ञासा से होती है लेकिन धीरे-धीरे यही जिज्ञासा लत और फिर विनाश का कारण बन जाती है।

इंटरनेट और डिजिटल तकनीक ने जहां ज्ञान के नए द्वार खोले हैं, वहीं नशे के कारोबार को भी नए साधन उपलब्ध कराए हैं। सोशल मीडिया, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स और डार्क वेब के माध्यम से मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त पहले से कहीं अधिक आसान हो गई है। अब नशे का सौदा किसी सुनसान गली तक सीमित नहीं बल्कि स्मार्टफोन की स्क्रीन तक पहुंच चुका है। यही कारण है कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में नशे की पहुंच चिंताजनक रूप से बढ़ती जा रही है। आज देश के अनेक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में नशीले पदार्थों की उपलब्धता को लेकर समय-समय पर गंभीर सवाल उठते रहे हैं। यह विडंबना ही है कि जिन परिसरों में देश के भविष्य का निर्माण होना चाहिए, वहां कुछ युवा अपने भविष्य को स्वयं नष्ट करने की राह पर बढ़ रहे हैं। आधुनिकता और स्वतंत्रता की गलत व्याख्या ने भी इस समस्या को बढ़ाया है। कई युवाओं को यह भ्रम होता है कि नशा उन्हें अधिक आत्मविश्वासी, रचनात्मक और आधुनिक बनाता है, जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। नशा व्यक्ति की सोचने-समझने की क्षमता को धीरे-धीरे समाप्त कर देता है। उसकी निर्णय लेने की शक्ति कमजोर हो जाती है, स्मरणशक्ति प्रभावित होती है, एकाग्रता घटती है और मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। जो युवा अपने जीवन में बड़े सपने लेकर आगे बढ़ता है, वही नशे की गिरफ्त में आकर अपनी प्रतिभा और संभावनाओं को स्वयं नष्ट कर देता है। यही कारण है कि नशे को केवल स्वास्थ्य समस्या नहीं बल्कि मानव संसाधन के विनाश की समस्या माना जाता है।

नशीले पदार्थों का सबसे घातक प्रभाव यह है कि वे व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों से गुलाम बना देते हैं। एक बार लत लग जाने पर व्यक्ति उसी प्रभाव को बनाए रखने के लिए लगातार अधिक मात्रा में नशा लेने लगता है। परिणामस्वरूप उसका शरीर कमजोर होने लगता है, भूख कम हो जाती है, वजन घटता है, आंखें लाल रहने लगती हैं, नींद प्रभावित होती है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है और अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई मामलों में व्यक्ति आत्मघाती प्रवृत्तियों का शिकार भी हो जाता है। इंजेक्शन के माध्यम से नशा करने वालों के सामने खतरा और भी गंभीर होता है। एक ही सुई के बार-बार उपयोग से एचआईवी, हेपेटाइटिस और अन्य संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ जाती है। यही कारण है कि नशा केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए भी गंभीर चुनौती बन जाता है।

नशे का अवैध व्यापार दुनिया के सबसे लाभकारी अपराधों में शामिल है। अरबों-खरबों रुपये का यह कारोबार अंतर्राष्ट्रीय तस्करी, आतंकवाद, संगठित अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराधों से गहराई से जुड़ा हुआ है। भारत की भौगोलिक स्थिति इसे गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल जैसे नशीले पदार्थों के प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों के बीच महत्वपूर्ण मार्ग बनाती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार और अन्य पड़ोसी क्षेत्रों से आने वाली तस्करी की खेपें भारत के लिए लगातार चुनौती बनी हुई हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि ड्रग्स का यह अवैध कारोबार अब अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रहा है। ड्रोन, एन्क्रिप्टेड संचार माध्यम, फर्जी पहचान और डिजिटल भुगतान प्रणालियां तस्करों को नई ताकत प्रदान कर रही हैं। ऐसे में केवल पारंपरिक पुलिसिंग से इस समस्या पर नियंत्रण संभव नहीं है। इसके लिए तकनीकी, सामाजिक और कानूनी स्तर पर व्यापक रणनीति की आवश्यकता है। भारत में हालांकि मादक पदार्थों की तस्करी और सेवन को रोकने के लिए कड़े कानून मौजूद हैं लेकिन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की चुनौती अभी भी बनी हुई है। नशे के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस, प्रशासन या सरकार की जिम्मेदारी नहीं हो सकती, यह समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। परिवारों को अपने बच्चों के साथ संवाद बढ़ाना होगा। शिक्षण संस्थानों को नशा विरोधी जागरूकता अभियान चलाने होंगे। धार्मिक और सामाजिक संगठनों को भी इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। दरअसल नशे के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार जागरूकता, शिक्षा और सकारात्मक वातावरण है। यदि युवाओं को बेहतर शिक्षा, रोजगार, खेल, कला, संस्कृति और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ा जाए तो वे नशे जैसे विनाशकारी रास्तों से दूर रह सकते हैं। हमें युवाओं को केवल नशे के दुष्परिणाम बताने तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि उन्हें जीवन का सकारात्मक उद्देश्य भी देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय नशा एवं मादक पदार्थ निषेध दिवस हमें यही संदेश देता है कि नशे के खिलाफ लड़ाई किसी एक दिन का अभियान नहीं बल्कि सतत सामाजिक आंदोलन है। यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो सबसे पहले उसकी युवा शक्ति को नशे के अंधकार से मुक्त करना होगा। देश की युवा सोच पर लगा यह ग्रहण तभी हटेगा, जब सरकार, समाज, परिवार और स्वयं युवा मिलकर इस चुनौती का सामना करेंगे। आज आवश्यकता इस बात की है कि युवाओं के हाथों में नशे की पुड़िया नहीं, ज्ञान की पुस्तक हो; उनकी आंखों में नशे का धुंधलापन नहीं, सपनों की चमक हो; और उनकी सोच पर नशे का ग्रहण नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का उज्ज्वल प्रकाश हो। यही नशा-मुक्त भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता है और यही विकसित भारत की सबसे मजबूत नींव भी।

लेखक- योगेश कुमार गोयल
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं तथा नशे के दुष्प्रभावों पर 1993 में पुरस्कृत पुस्तक मौत को खुला निमंत्रण लिख चुके हैं)

एआई और इंटरनेट से बढ़ती डिजिटल थकान: कारण और समाधान

आज का युग तकनीक का युग है और आज के इस तकनीक और डिजिटल युग में हर किसी में डिजिटल फटीग (डिजिटल थकान) तेजी से बढ़ती समस्या बनती जा रही है। दिनभर या यूं कहें कि लगातार स्क्रीन पर काम करना, बार-बार आने वाले नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग, ऑनलाइन बैठकों और एआई आधारित टूल्स पर बढ़ती निर्भरता के कारण लोगों में मानसिक थकान, एकाग्रता की कमी, आंखों में तनाव और चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए बनाए गए डिजिटल साधन कई बार मानसिक दबाव का कारण भी बन जाते हैं। इसलिए स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करना, नियमित अंतराल पर विश्राम लेना और डिजिटल संतुलन बनाए रखना आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

कहना गलत नहीं होगा कि मोबाइल या लैपटॉप पर बार-बार आने वाले नोटिफिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) द्वारा तैयार की जा रही सामग्री, स्क्रीन पर लगातार काम करने की आदत और विभिन्न एआई टूल्स के बढ़ते उपयोग के कारण आज लोगों में मानसिक और डिजिटल थकान तेजी से बढ़ रही है। विडंबना यह है कि जिन तकनीकों और टूल्स को हमारी उत्पादकता बढ़ाने के लिए बनाया गया था, वे ही अब एकाग्रता में कमी, तनाव और बर्नआउट का मुख्य कारण बन रहे हैं। ऑनलाइन लेक्चर, वर्चुअल मीटिंग्स, इंटरनेट पर उपलब्ध असीमित जानकारियों, रील्स और शॉर्ट वीडियोज ने लोगों को इस कदर बांध लिया है कि किताब पढ़ते समय भी ध्यान बार-बार मोबाइल फोन की ओर चला जाता है, जिसका सीधा असर हमारी स्मरण शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता पर भी पड़ रहा है। लगातार डिजिटल माध्यमों के संपर्क में रहने और एआई-आधारित टूल्स से मिलने वाले अलर्ट्स, रिमाइंडर्स व परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स के कारण आज मानसिक बोझ बढ़ रहा है।

पाठक जानते हैं कि आज शिक्षा से लेकर कार्यस्थल तक एआई कौशल सीखने पर विशेष जोर दिया जा रहा है, लेकिन जब हम एआई के उत्तरों पर पूरी तरह निर्भर होने लगते हैं, तो गहराई से सोचने, तर्क करने और नए समाधान खोजने की हमारी मौलिक व रचनात्मक क्षमता कमजोर पड़ने लगती है। इंटरनेट मीडिया पर स्क्रॉलिंग की कोई निश्चित सीमा नहीं होती और एआई एल्गोरिदम उपयोगकताओं के व्यवहार व रुचियों के आधार पर लगातार व्यक्तिगत व आकर्षक कंटेंट दिखाते रहते हैं, जिससे लोग कुछ मिनट के लिए प्लेटफॉर्म खोलकर भी वहां घंटों बिता देते हैं। इस इन्फॉर्मेशन ओवरलोड (सूचना की अधिकता) के कारण मानसिक संतुलन प्रभावित होता है और व्यक्ति थकान व भ्रम का शिकार हो जाता है। इस स्थिति से बचने के लिए गैर-जरूरी नोटिफिकेशन बंद करना, स्क्रीन टाइम सीमित रखना, प्रतिदिन सुबह और रात को कुछ समय डिजिटल डिवाइस से दूर रहना तथा हर आधे घंटे में छोटा ब्रेक लेना बेहद आवश्यक है।

वास्तव में, आज चिंता का विषय यह नहीं है कि एआई मानव रचनात्मकता का स्थान ले लेगा, बल्कि यह है कि उस पर अत्यधिक निर्भरता हमारी जिज्ञासा और स्वतंत्र सोच को सीमित कर देगी; इसलिए एआई का उपयोग केवल एक सहायक उपकरण के रूप में होना चाहिए।

बहरहाल, देश में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की हालिया रिपोर्ट बताती है कि भारत में अब लगभग 109 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जहां मोबाइल-इंटरनेट उपभोक्ता औसतन हर महीने 26.7 जीबी डेटा खर्च कर रहे हैं, तथा कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 133 करोड़ से अधिक हो गई है, जिससे स्पष्ट है कि डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत होने के साथ भारत तेजी से एक डिजिटल समाज और डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है।

अंत में निष्कर्ष के तौर पर यही कहूंगा कि डिजिटल क्रांति और एआई निश्चित रूप से प्रगति के बड़े माध्यम हैं, लेकिन इनका अनियंत्रित उपयोग मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है। भारत के तेजी से बढ़ते डिजिटल समाज में डिजिटल वेलबीइंग (डिजिटल कल्याण) को प्राथमिकता देना अब वैकल्पिक नहीं, बल्कि अनिवार्य हो गया है। तकनीक हमारी सोच और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए है, न कि उसे नियंत्रित करने के लिए। अतः सजगता, सीमित उपयोग और समय-समय पर डिजिटल डिटॉक्स अपनाकर ही हम इस बढ़ते मानसिक तनाव से बच सकते हैं और तकनीकी विकास का वास्तविक लाभ उठा सकते हैं।

सुनील कुमार महला
फ्रीलांस राइटर, कॉलमिस्ट व युवा साहित्यकार, पिथौरागढ़, उत्तराखंड

पेंशन पर राजनीति नहीं, स्थायी नीति बने

हिमाचल प्रदेश सहित पूरे देश में इस समय पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली को लेकर निरंतर बहस जारी है। पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस), राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और हाल ही में प्रस्तावित यूपीएस पेंशन और विभिन्न पेंशन सुधारों के बीच सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि सेवानिवृत्ति के बाद किसी कर्मचारी की आर्थिक सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। वास्तव में पेंशन केवल एक आर्थिक लाभ नहीं, बल्कि वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवन जीने का आधार है।

कोई भी कर्मचारी अपने जीवन के लगभग तीन से चार दशक सार्वजनिक सेवा, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास कार्यों में समर्पित करता है। अपने कार्यकाल के दौरान वह राज्य और समाज के निर्माण में योगदान देता है। सेवानिवृत्ति के बाद नियमित वेतन समाप्त हो जाता है, लेकिन जीवन की आवश्यकताएं समाप्त नहीं होतीं। बढ़ती आयु के साथ स्वास्थ्य संबंधी खर्च, देखभाल, दवाइयों और पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता जाता है। ऐसे समय में पेंशन व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा के साथ मानसिक संतुलन और सामाजिक सम्मान भी प्रदान करती है। पिछले दिनों शिमला में एक प्रेस वार्ता में एनपीएस/ओपीएस पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इस बारे में 2022 की नीति पर चलने का संकेत दिया है और जयराम ठाकुर का नाम विशेष रूप से लेकर उन्होंने हिमाचल भाजपा में उनके नेतृत्व की अहमियत को भी रेखांकित कर दिया है।

चूंकि पेंशन और अन्य वित्तीय लाभों के कारण कर्मचारियों के बीच में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ज्यादा लोकप्रिय नहीं हैं, लिहाजा आजकल सोशल मीडिया में जयराम ठाकुर को पुन: भाजपा की कमान मिलने के संकेतों के बाद टिप्पणियों की बाढ़ सी आई हुई है। 2003 के बाद सरकारी सेवा में लगे सेवारत्त कर्मचारियों और सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग में अपनी पेंशन सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से बेचैनी बढ़ी है क्योंकि पिछली बार विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कर्मचारियों को विधानसभा चुनाव लड़ने और अपनी पेंशन सुरक्षित करने की चुनौती दे चुके हैं। राजनीति में बड़े नेताओं के संकेत अक्सर शब्दों से अधिक प्रभाव रखते हैं, इसलिए इस बयान को केवल पेंशन नीति पर टिप्पणी नहीं, बल्कि 2027 से पहले पार्टी के संभावित नेतृत्व की दिशा बताने वाले संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। भारत में जीवन प्रत्याशा दर पिछले सात दशकों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। स्वतंत्रता के समय जहां औसत आयु लगभग 32 वर्ष थी, वहीं आज यह 70 वर्ष से अधिक हो चुकी है। चिकित्सा सुविधाओं में सुधार और जीवन में समृद्धि के कारण लोग अधिक समय तक जीवित रह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में यह विषय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्रदेश के हजारों कर्मचारी दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में कठिन परिस्थितियों में सेवाएं देते हैं। शिक्षा, बिजली, पानी, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिसकर्मी और अन्य विभागों के कर्मचारी वर्षों तक चुनौतीपूर्ण वातावरण में कार्य करते हैं। इसलिए कर्मचारियों का यह तर्क स्वाभाविक है कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें ऐसी व्यवस्था मिले जो भविष्य की आर्थिक चिंताओं से मुक्त रख सके। यही कारण है कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली के बाद कर्मचारी संगठन इसके स्थायी संरक्षण की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर सरकारों के सामने वित्तीय चुनौतियां भी कम नहीं हैं।

हिमाचल प्रदेश जैसे सीमित संसाधनों वाले राज्य में वेतन और पेंशन पर होने वाला व्यय बजट का बड़ा हिस्सा लेता है। बढ़ता सार्वजनिक ऋण, प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति, आधारभूत ढांचे की आवश्यकताएं और विकास योजनाओं का खर्च सरकार के लिए निरंतर चुनौती बना हुआ है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि परंपरागत पेंशन प्रणाली में भविष्य का पूरा वित्तीय दायित्व सरकार पर होता है, जबकि नई प्रणालियों में इस दायित्व को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। विश्व के अनेक देशों ने इसी सोच के आधार पर अपनी पेंशन व्यवस्थाओं को विकसित किया है। डेनमार्क, नीदरलैंड, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड जैसे देशों में पेंशन व्यवस्था को सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। आधुनिक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा यही कहती है कि वृद्धावस्था में कोई भी व्यक्ति आर्थिक असुरक्षा का शिकार न हो। पेंशन बहस का एक महत्वपूर्ण पक्ष समानता और न्याय का भी है। अक्सर यह प्रश्न उठता है कि जहां सरकारी कर्मचारी दशकों तक सेवा देने के बाद पेंशन के लिए विभिन्न नियमों और प्रक्रियाओं का सामना करते हैं, वहीं कई जनप्रतिनिधियों को अपेक्षाकृत कम अवधि के कार्यकाल के बाद भी पेंशन लाभ प्राप्त हो जाते हैं।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि सभी वर्गों के लिए नियमों में पारदर्शिता, संतुलन और न्याय दिखाई दे। आज आवश्यकता किसी एक व्यवस्था के पक्ष या विपक्ष में खड़े होने की नहीं, बल्कि ऐसे समाधान खोजने की है जो कर्मचारियों की वृद्धावस्था सुरक्षा और सरकार की वित्तीय क्षमता दोनों का ध्यान रखें। इसके लिए विशेषज्ञों, वित्तीय संस्थानों, कर्मचारी संगठनों और सरकार के बीच रचनात्मक संवाद आवश्यक है। पेंशन सुधारों का उद्देश्य केवल व्यय कम करना नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और टिकाऊ व्यवस्था तैयार करना होना चाहिए। अंतत: पेंशन का प्रश्न केवल आर्थिक नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा से जुड़ा विषय है। कोई भी समाज अपने उन लोगों को नहीं भूल सकता जिन्होंने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय सार्वजनिक सेवा और राष्ट्र निर्माण में लगाया हो। वृद्धावस्था में सुरक्षा, सम्मान और आत्मविश्वास प्रदान करना किसी भी संवेदनशील और कल्याणकारी राज्य का दायित्व है। इसलिए पेंशन पर चल रही बहस को राजनीतिक दृष्टिकोण से ऊपर उठाकर सामाजिक न्याय, आर्थिक विवेक और मानवीय संवेदना के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। यही दृष्टिकोण भविष्य में एक संतुलित, न्यायपूर्ण और स्थायी पेंशन व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

अनुज आचार्य
लेखक बैजनाथ से हैं

आलेख

स्मार्टफोन संयमित उपयोग की वैश्विक जरूरत

विज्ञान और तकनीक ने मानव सभ्यता को अभूतपूर्व गति प्रदान की है। आज का युग डिजिटल युग है, जहां एक क्लिक पर पूरी दुनिया हमारी हथेली में सिमट आई है। स्मार्टफोन ने संचार, शिक्षा, व्यापार, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शासन और सामाजिक संबंधों को नई दिशा दी है। लेकिन हर तकनीकी क्रांति अपने साथ कुछ गंभीर चुनौतियां भी लेकर आती है। स्मार्टफोन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह जितना बड़ा वरदान सिद्ध हुआ है, उतना ही बड़ा अभिशाप भी बनता जा रहा है। विशेष रूप से बच्चों और किशोरों पर इसके दुष्प्रभावों ने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है। आज विश्वभर में यह स्वीकार किया जा रहा है कि स्मार्टफोन केवल एक उपकरण नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है, जिसका विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है। दुर्भाग्यवश, विवेक और अनुशासन के अभाव में इसका नकारात्मक पक्ष अधिक मुखर हो रहा है। स्मार्टफोन की लत बच्चों और युवाओं में मानसिक तनाव, अवसाद, एकाकीपन, हिंसक प्रवृत्तियों, अश्लीलता, साइबर अपराध और सामाजिक विघटन का कारण बन रही है। यही कारण है कि आज केवल परंपरागत समाज और विकासशील देश ही नहीं, बल्कि विकसित देश भी इस चुनौती से निपटने के लिए कठोर कदम उठा रहे हैं।

हाल ही में भारत के हरियाणा के नूंह जिले के सुखपुरी गांव की पहल ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। गांव की पहचान साइबर अपराध के केंद्र के रूप में बनने लगी थी। इससे आहत होकर ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से स्मार्टफोन त्यागने और बेसिक फोन अपनाने का निर्णय लिया। यह केवल मोबाइल तोड़ने की घटना नहीं, बल्कि समाज की उस पीड़ा की अभिव्यक्ति है, जो तकनीक के दुरुपयोग से उत्पन्न हुई है। गांव के युवाओं का विरोध भी स्वाभाविक है, क्योंकि आज शिक्षा, रोजगार, डिजिटल भुगतान और सरकारी सेवाएं स्मार्टफोन पर निर्भर हैं। इस घटना ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा किया है-क्या समाधान तकनीक का बहिष्कार है या उसके विवेकपूर्ण उपयोग का संस्कार? विश्व के अनेक देशों ने इस प्रश्न पर गंभीर चिंतन आरंभ कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, नीदरलैंड, चीन और अमेरिका जैसे देशों में बच्चों और किशोरों के स्मार्टफोन उपयोग को नियंत्रित करने की दिशा में अनेक पहलें हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया ने किशोरों के सोशल मीडिया उपयोग पर आयु-सीमा तय करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। फ्रांस ने स्कूलों में स्मार्टफोन प्रतिबंध लागू किया है। ब्रिटेन में भी स्कूलों में मोबाइल उपयोग को सीमित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अमेरिका में सोशल मीडिया कंपनियों के विरुद्ध मुकदमे दायर हुए हैं और उन पर भारी जुमार्ने लगाए गए हैं। इन पहलों का उद्देश्य तकनीक का विरोध नहीं, बल्कि बच्चों के मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है।

वास्तव में स्मार्टफोन जहां वरदान है, वहीं अभिशाप भी है। इससे ज्ञान का भंडार भी उपलब्ध है और भ्रम का संसार भी। यह शिक्षा का माध्यम भी है और अश्लीलता तथा हिंसा का प्रवेश-द्वार भी। यह रोजगार के अवसर भी देता है और साइबर अपराध की राह भी खोलता है। आज अनेक युवा रातों-रात अमीर बनने की लालसा में साइबर ठगी, सेक्सटॉर्शन, ऑनलाइन जुआ और डिजिटल धोखाधड़ी जैसे अपराधों में फंस रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैल रही अश्लील सामग्री, फेक न्यूज, नफरत और ट्रोल संस्कृति ने सामाजिक मूल्यों को गहरी चोट पहुंचाई है। सबसे अधिक चिंता का विषय बच्चों और किशोरों का मानसिक स्वास्थ्य है। शोध बताते हैं कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम से बच्चों की एकाग्रता, स्मरण शक्ति और रचनात्मक क्षमता प्रभावित होती है। नींद में

कमी, चिड़चिड़ापन, अवसाद, चिंता, आत्महत्या की प्रवृत्ति और सामाजिक अलगाव जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। परिवारों में संवाद कम हुआ है और डिजिटल निकटता के बावजूद भावनात्मक दूरियां बढ़ी हैं। बच्चे खेल के मैदानों से दूर होकर आभासी दुनिया में खोते जा रहे हैं।

विशेषत: ह्यस्मार्टफोन एक दुधारी तलवार हैह्ल। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और अत्याधुनिक संचार माध्यमों ने इस चुनौती को और अधिक जटिल बना दिया है। एआई जहां शिक्षा, चिकित्सा, अनुसंधान और प्रशासन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है, वहीं इसके दुरुपयोग की आशंकाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। डीपफेक वीडियो, फर्जी ऑडियो, साइबर ठगी, पहचान की चोरी, फेक न्यूज और डिजिटल ब्लैकमेल जैसे अपराधों में एआई का इस्तेमाल चिंताजनक स्तर तक बढ़ गया है। स्मार्टफोन इस पूरी प्रक्रिया का सबसे सुलभ और प्रभावी माध्यम बन गया है। एक साधारण मोबाइल फोन के माध्यम से आज कोई भी व्यक्ति एआई आधारित एप्लीकेशनों का उपयोग कर नकली तस्वीरें और वीडियो तैयार कर सकता है, भ्रामक सूचनाएं फैला सकता है या साइबर अपराधों को अंजाम दे सकता है। विशेष रूप से किशोर और युवा, जिनके पास तकनीकी कौशल तो है लेकिन नैतिक प्रशिक्षण और परिपक्वता का अभाव है, वे अनजाने में अथवा त्वरित लाभ की लालसा में ऐसे कृत्यों में संलिप्त हो सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि एआई और स्मार्टफोन के उपयोग के साथ-साथ डिजिटल नैतिकता, मानवीय मूल्यों और कानूनी जिम्मेदारियों का भी समुचित प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि तकनीक मानवता के विकास का साधन बने, विनाश का नहीं। इस संदर्भ में यह कथन अत्यंत प्रासंगिक है-ह्यविज्ञान बिना विवेक के विनाश का कारण बनता है, जबकि विवेक के साथ वही विज्ञान मानवता का वरदान बन जाता है।

ऐसी स्थिति में भारत में भी व्यापक राष्ट्रीय विमर्श की आवश्यकता है। भारत विश्व की सबसे युवा आबादी वाला देश है और एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। यदि भारत को विश्वगुरु के रूप में अपनी भूमिका निभानी है, तो उसे तकनीक और मानवीय मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित करना होगा। भारत द्वारा निर्मित नीतियां न केवल देश, बल्कि विश्व के लिए भी मार्गदर्शक बन सकती हैं। इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं-पहला, बच्चों और किशोरों के लिए स्मार्टफोन उपयोग की आयु-सीमा और समय-सीमा निर्धारित की जाए। एक निश्चित आयु तक बच्चों को केवल आवश्यक और नियंत्रित डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

दूसरा, स्कूलों में साइबर साक्षरता और डिजिटल नैतिकता को पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाए। बच्चों को केवल तकनीक का उपयोग ही नहीं, बल्कि उसके दुष्परिणामों और कानूनी पहलुओं की जानकारी भी दी जानी चाहिए। तीसरा, अभिभावकों को डिजिटल पैरेंटिंग का प्रशिक्षण दिया जाए। बच्चों को मोबाइल थमाकर जिम्मेदारी पूरी नहीं होती-उन्हें मार्गदर्शन, संवाद और संस्कार भी देने होंगे। चौथा, सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। हानिकारक और अश्लील सामग्री पर प्रभावी नियंत्रण, आयु सत्यापन और एल्गोरिदम की पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। पांचवां, युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास और रचनात्मक अवसरों का विस्तार किया जाए, ताकि वे त्वरित धनार्जन के प्रलोभन में अपराध की ओर न बढ़ें।

भारतीय संस्कृति सदैव संयम की संस्कृति रही है। हमारे ऋषियों ने सिखाया है कि किसी भी साधन का मूल्य उसके उपयोग में निहित होता है। आग भोजन भी पका सकती है और घर भी जला सकती है-दोष आग का नहीं, उपयोगकर्ता का होता है। यही बात स्मार्टफोन पर भी लागू होती है। आज आवश्यकता डिजिटल दुनिया से कटने की नहीं, बल्कि डिजिटल जिम्मेदारी, साइबर साक्षरता और संयमित उपयोग की है। तकनीक का विरोध समाधान नहीं है, बल्कि उसके साथ नैतिकता, विवेक और मानवीय मूल्यों का समन्वय ही स्थायी समाधान है। स्मार्टफोन मानव की सेवा का साधन बने, मानव का स्वामी नहीं-इसी में व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का कल्याण निहित है।

(लेखक- ललित गर्ग)

संक्षिप्त वार्ता

मकान की सीढ़ियां ढहीं, बच्ची समेत पांच महिलाओं और पालतू कुत्ते को सुरक्षित निकाला

नई दिल्ली, वेब वार्ता

उत्तर दिल्ली के मल्का गंज इलाके में गुरुवार दोपहर एक मकान की सीढ़ियां अचानक ढह जाने से अफरा-तफरी मच गई। हादसे के समय कुछ लोग दूसरी मंजिल पर फंस गए थे। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव अभियान चलाकर बच्ची समेत पांच महिलाओं और एक पालतू कुत्ते को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

दमकल विभाग के अनुसार दोपहर करीब 1:33 बजे रूप नगर क्षेत्र के तिलक चौक, सब्जी मंडी स्थित मकान संख्या 2088 में मकान ढहने की सूचना मिली थी। शुरूआती जानकारी के आधार पर एक वाटर टेंडर, एक वाटर बाउजर, एक आईआरटी और एक एमसीएफआर को मौके पर भेजा गया। घटनास्थल पर पहुंची टीम को पता चला कि मकान की पहली मंजिल की सीढ़ियां गिर गई हैं, जिससे दूसरी मंजिल पर मौजूद लोग नीचे नहीं उतर पा रहे थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त दमकल कर्मियों, सुरक्षा बेल्ट और बचाव उपकरणों की मांग की गई। इसके बाद अतिरिक्त टीमों को मौके पर भेजा गया और सावधानीपूर्वक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बचाव अभियान के दौरान मानसी (45), उनकी बेटी अंजलि (24), पायल (21), पांच माह की बच्ची नीरू और दिव्यांग महिला कविता (40) को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके अलावा परिवार के पालतू कुत्ते को भी रेस्क्यू कर लिया गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। संबंधित एजेंसियां मकान की स्थिति और हादसे के कारणों की जांच कर रही हैं।

आपातकाल के बारे में नई पीढ़ी को पता होना चाहिए : सूद

नई दिल्ली, वेब वार्ता

दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक में 'आपातकाल' पर अध्याय जोड़े जाने पर गुरुवार को प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है, ह्लअभिव्यक्ति की आजादी क्या है? अघोषित आपातकाल और घोषित आपातकाल में क्या अंतर है? नई पीढ़ी को यह सब पता होना चाहिए।ह्व

मंत्री सूद ने आज दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि एनसीईआरटी ने आपातकाल के दौरान लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी को किस प्रकार से छीना गया, उसको एनसीईआरटी ने नई पीढ़ी को बताने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को यह सब पता होना चाहिए, ताकि कोई भी फिर से ऐसी कोशिश न कर सकें।

मंत्री सूद ने इससे पर सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय है। सत्ता बचाने के लिए लगाए गए आपातकाल ने देशवासियों के मौलिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर गहरा आघात किया। उन्होंने कहा कि ह्लसंविधान हत्या दिवसह्व पर उन सभी लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन, जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा और नागरिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए संघर्ष किया। उनका साहस और त्याग सदैव राष्ट्र को प्रेरित करता रहेगा।

एमसीडी सदन में अग्निकांड की घटनाओं पर हंगामा, विपक्ष ने उठाए सवाल

नई दिल्ली, वेब वार्ता

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की साधारण सभा की बैठक गुरुवार को नगर निगम मुख्यालय सिविक सेंटर में आयोजित की गई। बैठक की शुरूआत शोक प्रस्ताव के साथ हुई। बैठक के दौरान आम आदमी पार्टी (आआपा), कांग्रेस और इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के पार्षदों ने दिल्ली में लगातार सामने आ रही आगजनी की घटनाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों ने अग्निकांड की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रशासन और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी (आआपा) के विधायक एवं एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने कहा कि दिल्ली में लगातार अग्निकांड की घटनाएं सामने आ रही हैं।

नियमों का पालन नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई : आशीष सूद

दिल्ली में 923 कोचिंग सेंटरों का होगा फायर ऑडिट

दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी के कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने बताया कि शहर में करीब 923 से 924 कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं और इन सभी का अगले एक महीने के भीतर फायर ऑडिट और सुरक्षा निरीक्षण कराया जाएगा।

नई दिल्ली, वेब वार्ता

फाईल फोटो

आशीष सूद ने मीडिया से कहा कि कोचिंग सेंटरों के लिए नियम और कानून तैयार करने के उद्देश्य से गठित समिति की बैठक बुलाई जा चुकी है। यह समिति गौबा कमेटी की सिफारिशों के आधार पर बनाई गई है। उन्होंने बताया कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को इस पूरी प्रक्रिया के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।

दिल्ली सरकार के मंत्री ने कहा कि नगर निगम के साथ सभी संबंधित एजेंसियों को मिलकर एक महीने के भीतर सभी 923-924 कोचिंग सेंटरों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान फायर सेफ्टी, सुरक्षा मानकों और अन्य जरूरी दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन कोचिंग संस्थानों के दस्तावेज पूरे नहीं होंगे या जो सुरक्षा ऑडिट में तय मानकों पर खरे नहीं उतरेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें सील भी किया जा सकता है।

आशीष सूद ने यह भी बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर जल्द ही एक नया कानून लाया जाएगा। इस कानून में कोचिंग संस्थानों की फीस से लेकर संचालन और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जाएगा। वहीं, कक्षा 9 की एनसीईआरटी किताब में आपातकाल (इमरजेंसी) का नया अध्याय शामिल किए जाने के सवाल पर भी दिल्ली सरकार के मंत्री ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को यह जानना चाहिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है और घोषित तथा अघोषित आपातकाल में क्या अंतर होता है। मंत्री आशीष सूद ने कहा कि देश के युवाओं को यह भी पता होना चाहिए कि आपातकाल के दौरान किस प्रकार की घटनाएं और अत्याचार हुए थे। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े ऐसे विषयों की जानकारी नई पीढ़ी तक पहुंचना बेहद जरूरी है।

दिल्ली में ससुरालवालों पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए महिला ने की आत्महत्या

नई दिल्ली, वेब वार्ता। दिल्ली के नांगलोई इलाके में स्थित ससुराल में एक 24 वर्षीय महिला ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले उसने दो वीडियो रिकॉर्ड किए, जिनमें वह अपने पति और ससुरालवालों पर लगातार उत्पीड़न का आरोप लगाती नजर आ रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, घटना की सूचना सोमवार सुबह 11:09 बजे नांगलोई पुलिस स्टेशन को मिली। सूचना में बताया गया कि नांगलोई एक्सटेंशन की रहने वाली 26 वर्षीय महिला को संजय गांधी मेमोरियल (एसजीएम) अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे अस्पताल पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया।

भाजपा में शामिल होने के बाद राघव चड्ढा का बड़ा हमला-बोले

सही समय पर छोड़ दी थी पार्टी

नई दिल्ली, वेब वार्ता

हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि वह सही समय पर आम आदमी पार्टी से अलग हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि कथित बेअदबी प्रकरण से जुड़े वास्तविक दृश्य को छिपाने के लिए झूठी रिपोर्ट तैयार कराई गई, जिससे पूरे मामले पर संदेह और गहरा गया है।

राघव चड्ढा ने कहा कि जिस प्रकार कथित बेअदबी प्रकरण को लेकर घटनाक्रम सामने आए हैं, उससे स्पष्ट हो गया है कि वास्तविक तथ्यों को छिपाने का प्रयास किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वास्तविकता को छिपाने के लिए झूठी रिपोर्ट तैयार कराई, जिसका अब खुलासा हो चुका है।

उन्होंने कहा कि यदि संबंधित दृश्य वास्तविक नहीं था तो फिर उसे झूठा साबित करने के लिए अलग से रिपोर्ट तैयार कराने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। राघव चड्ढा ने भगवंत मान को "पंथ विरोधी" बताते हुए कहा कि इस पूरे घटनाक्रम से सिख समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। उल्लेखनीय है कि श्री अकाल तख्त द्वारा भगवंत मान को "गुरु दोखी" करार दिए जाने को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है। इसी बीच गुरुग्राम पुलिस ने दो प्रयोगशाला संचालकों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पंजाब पुलिस के कुछ अधिकारियों ने कथित तौर पर धन देकर उनसे ऐसी रिपोर्ट तैयार कराई, जिसमें संबंधित दृश्य को झूठा बताया गया था।

भविष्य पर विचार करने की अपील

राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के सिख विधायकों से भी अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सिख समाज यह जानना चाहता है कि पार्टी के विधायक सिख पंथ और श्री अकाल तख्त के साथ खड़े हैं या फिर भगवंत मान का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की व्यापक जांच की मांग करते हुए कहा कि यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि झूठी रिपोर्ट तैयार कराने में किन-किन लोगों की भूमिका रही, धन किसने उपलब्ध कराया और क्या सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। राघव चड्ढा ने कहा कि सिख समाज की दो प्रमुख मांगें हैं। पहली, भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद से तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और दूसरी, नए बेअदबी कानून के तहत पहली प्राथमिकी उनके विरुद्ध दर्ज की जानी चाहिए। आम आदमी पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए राघव चड्ढा ने कहा कि ईश्वर की कृपा से वह समय रहते ऐसी पार्टी से अलग हो गए, जिस पर पंथ विरोधी होने के आरोप लग रहे हैं। उन्होंने संकेतों में अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी अपने राजनीतिक भविष्य पर विचार करने की अपील की।

सीएम श्री स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए 265 करोड़ के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

नई दिल्ली, वेब वार्ता

दिल्ली सरकार ने 75 सीएम श्री स्कूलों में आधुनिक, सुरक्षित और बेहतर सुविधाओं से लैस बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 264 करोड़ 90 लाख 88 हजार रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की अध्यक्षता में बुधवार को हुई व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री ने गुरुवार को एक विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत स्कूलों के प्रवेश द्वारों का आधुनिक स्वरूप में निर्माण, संशोधन और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उन पर सीएम श्री का नया लोगो और स्कूल का नाम प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भवनों में सीलन और नमी की समस्या दूर करने, वॉटरप्रूफिंग, आंतरिक एवं बाहरी पेंटिंग, प्लास्टर की मरम्मत, बाउंड्री वॉल एवं फेंसिंग का निर्माण अथवा मरम्मत, शौचालयों में सुधार, पेयजल सुविधा में सुधार, सीवर एवं ड्रेनेज व्यवस्था को बेहतर बनाने, आवश्यकता के अनुरूप खेल सुविधाओं का विकास, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की मरम्मत, मल्टीपरपज हॉल का नवीनीकरण और आवश्यकता अनुसार अन्य मरम्मत कार्य किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिकल कार्यों के तहत अग्नि सुरक्षा से जुड़े कार्य किए जाएंगे। खराब एलईडी लाइट, सीलिंग फैन, एग्जॉस्ट फैन और पीए (पब्लिक एड्रेस) सिस्टम को बदला जाएगा, ताकि पूरे परिसर में घोषणाएं और आपातकालीन सूचनाएं प्रभावी ढंग से प्रसारित की जा सकें। स्कूल परिसरों में हाई मास्ट लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी।

मल्टीपरपज हॉल एवं कंप्यूटर लैब में एयर कंडीशनिंग, स्टेज लाइटिंग, सीएम श्री लोगो युक्त एलईडी साइनेज एवं एलईडी बोर्ड, इनबिल्ट आरओ वॉटर कूलर, मुख्य विद्युत पैनलों का अपग्रेडेशन और नई वायरिंग, री-वायरिंग, पावर पॉइंट और लैन पॉइंट उपलब्ध कराए जाएंगे। विशेष प्राथमिकता वाले कार्यों के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए रैंप, टैक्टाइल पाथ और हैंडरेल जैसी दिव्यांगजन-अनुकूल सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही सीसीटीवी, कंपाउंड लाइटिंग और खेल मैदानों का विकास भी किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य केवल भवनों की मरम्मत करना नहीं, बल्कि सरकारी विद्यालयों को ऐसे आधुनिक शिक्षण परिसरों में विकसित करना है, जहां विद्यार्थियों को सुरक्षित, समावेशी, तकनीक-सक्षम और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध हो। यह प्रस्ताव दिल्ली के सरकारी विद्यालयों की आधारभूत संरचना को नई दिशा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अगले साल के अंत तक पूरा करने का रखा गया है लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना के अंतर्गत स्कूल परिसरों का स्वरूप भी पूरी तरह बदला जाएगा। आधुनिक डिजाइन वाले सीएम श्री प्रवेश द्वार विकसित किए जाएंगे। जहां बाउंड्री वॉल अच्छी स्थिति में है वहां आवश्यकतानुसार मामूली मरम्मत की जाएगी और ग्रिट फिनिश को बरकरार रखा जाएगा। फेंसिंग को आकर्षक विपरीत रंगों से रंगा जाएगा। खेल मैदानों में आधुनिक आउटडोर गैलरी विकसित की जाएगी, जिसका उपयोग आउटडोर कक्षाओं, मनोरंजन, इंटरैक्टिव गतिविधियों तथा सहयोगात्मक शिक्षण के लिए किया जा सकेगा। बास्केटबॉल कोर्ट में नया टर्फ बिछाया जाएगा। यह सारा कार्य अगल साल के अंत तक पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

28 जून से जंतर-मंतर पर अनशन करेंगे सोनम वांगचुक, जेनेवा से किया ऐलान

नई दिल्ली, 25 जून (वेब वार्ता)। प्रसिद्ध शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 28 जून से दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनशन शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने यह घोषणा स्विट्जरलैंड के जेनेवा से करते हुए कहा कि यदि सरकार उनकी प्रमुख मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, तो वह रविवार से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे। सोनम वांगचुक ने जेनेवा से जारी एक दृश्य संदेश में कहा कि वह इस समय संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के बाहर स्थित प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड से लौटने के बाद वह आंदोलनकारियों से मिलने वाले थे और यह देखने वाले थे कि उनकी मांगों पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक पहल दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को शिक्षा, पर्यावरण और संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी जवाबदेही स्पष्ट करनी चाहिए। विशेष रूप से लद्दाख से जुड़े पर्यावरणीय और सांस्कृतिक मुद्दों पर सरकार को ठोस जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है।

उपराज्यपाल ने संजय झील के जीर्णोद्धार और कायाकल्प के कामों का लिया जायजा

नई दिल्ली, वेब वार्ता

दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने गुरुवार को पूर्वी दिल्ली स्थित संजय झील का दौरा करते हुए वहां चल रहे जीर्णोद्धार और कायाकल्प के कामों का जायजा लिया। मौके पर निरीक्षण के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने उपराज्यपाल को 52 एकड़ में फैली झील और इसके आस-पास के 165 एकड़ के संरक्षित जंगल को फिर से जीवंत करने की चरणबद्ध कार्ययोजना के बारे में जानकारी दी।

उपराज्यपाल सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि इस महत्वपूर्ण 'ब्लू-ग्रीन' (जल और हरियाली वाले) क्षेत्र को हर मौसम में इस्तेमाल लायक और साफ-सुथरी मनोरंजक जगह बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने डल्लूपुरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से साफ पानी की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड को संचालित पाइपलाइन की मरम्मत का काम तेजी से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि झील को बचाने और उसे फिर से जीवंत करने के लिए लगातार खरपतवार हटाने, काई (शैवाल) साफ करने और जियो-टेक्सटाइल तकनीक का इस्तेमाल करके तटबंधों की ढलानों को मजबूत करने का काम पहले से ही चल रहा है। आने वाले चरणों में रुके हुए पानी के बहाव को ठीक करने, भूजल रिचार्ज को बढ़ाने के लिए बायो-स्वेल्स लगाने, बायो-रेमेडिएशन के उपाय करने और पानी में घुली ऑक्सीजन का स्तर बेहतर बनाने के लिए एरेटर और फव्वारे लगाने पर ध्यान दिया जाएगा।

ईडी ने 600 करोड़ रुपए से अधिक के कथित दवा खरीद घोटाले में डीजीएचएस से मांगे दस्तावेज

नई दिल्ली, वेब वार्ता

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग से 600 करोड़ रुपए से अधिक के कथित दवा खरीद घोटाले के सिलसिले में दस्तावेज मांगे हैं। सूत्रों ने बताया कि ईडी ने मेडिकल उपकरणों की खरीद में कथित घोटाले को लेकर जांच शुरू की है। इस मामले में एजेंसी ने मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स से जुड़े टेंडर, पेमेंट और ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड भी मांगे हैं।

ईडी की दिल्ली जोन-2 टीम ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के निदेशक को एक पत्र भेजा है, जिसमें सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी (सीपीए) और डीजीएचएस की ओर से की गई खरीद से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है। जांच के दायरे में एक्स-रे मशीन, सी-आर्म रेडियोलॉजिकल उपकरण, एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट (ओआरएस), बेड शीट, लिनेन सामान, सर्जिकल सामान, ड्रेसिंग, स्यूचर, कैनुला, दस्ताने और दवाइयों जैसी खरीद शामिल हैं।

सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसी ने तथाकथित घोटाले की जांच करते हुए टेंडर प्रक्रिया, तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन, ठेके देने की प्रक्रिया, सामान की सप्लाई, जांच, मंजूरी और पेमेंट रिलीज से जुड़े रिकॉर्ड भी मांगे हैं। इसके अलावा ईडी ने उन कंपनियों, मैन्युफैक्चरर्स, ओईएम और डिस्ट्रीब्यूटर्स से जुड़े लेन-देन की जानकारी मांगी है, जिनसे मेडिकल उपकरण खरीदे गए थे। जिन कंपनियों और उपकरणों से जुड़े रिकॉर्ड मांगे गए हैं, उनमें पोर्टेबल एक्स-रे मशीन, सी-आर्म मशीन और एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन बनाने वाली कंपनियां शामिल हैं। ईडी इस पूरे मामले में यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मेडिकल सामान की खरीद प्रक्रिया में कोई अनियमितता, वित्तीय गड़बड़ी या मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला तो नहीं है।

सूत्रों ने कहा कि फिलहाल जांच जारी है और विभाग से मांगे गए दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले, दिल्ली सरकार की एंटी-करप्शन ब्रांच (एसीबी) ने सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी (सीपीए) के पूर्व प्रमुख विनोद कुमार रंगा को दवाओं, सर्जिकल सामान, इस्तेमाल होने वाली चीजों और मेडिकल उपकरणों की गैर-कानूनी खरीद में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। दवा खरीद घोटाला इस महीने की शुरूआत में सीपीए की ओर से दवाओं और मेडिकल उपकरणों की खरीद में कथित अनियमितताओं के कारण चर्चा में आया था। इस घटना के बाद कई डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ जांच एजेंसियों की नजर में आए। वहीं, दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मुकदमा दर्ज किया गया था।

दिल्ली स्वास्थ्य खरीद घोटाले में ईडी ने बढ़ाया जांच का दायरा

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में हुई कथित अनियमितताओं पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपना शिकंजा कस दिया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए ईडी ने स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक को पत्र लिखकर चिकित्सा उपकरणों और दवाओं की खरीद से जुड़े सभी रिकॉर्ड तलब किए हैं। जांच एजेंसी अब टेंडर प्रक्रिया, वित्तीय मूल्यांकन और भुगतान के हर पहलू की गहन पड़ताल कर रही है।

नई दिल्ली, वेब वार्ता

जांच का मुख्य केंद्र पोर्टेबल एक्स-रे मशीनें, सी-आर्म उपकरण और एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन जैसी उच्च मूल्य वाली खरीद है। इसके अलावा, दवाओं, सर्जिकल सामान और लिनन आइटम की खरीद का भी ब्यौरा मांगा गया है। ईडी विशेष रूप से प्रोग्नोसिस, किरण मेडिकल सिस्टम्स और ड्रेगर जैसी संस्थाओं और उनके वितरकों के साथ हुए लेनदेन की भूमिका की जांच कर रही है, जिन्हें ये अनुबंध आवंटित किए गए थे।

डीजीएचएस से मांगा 650 करोड़ के टेंडर्स और वेंडर्स का पूरा ब्यौरा

650 करोड़ के घोटाले का मामला

यह पूरा प्रकरण दिल्ली सरकार की सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी में 650 करोड़ रुपये के कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है। नियमों का उल्लंघन कर चहेते वेंडरों को टेंडर देने और बिना मांग के बड़ी मात्रा में उपकरणों की खरीद के आरोपों के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्व में विजिलेंस टीम ने छापेमारी की थी और कई अधिकारियों पर गाज भी गिर चुकी है।

दिल्ली: सीलमपुर में 17 वर्षीय युवक की हत्या का मामला सुलझा, पुलिस ने दो नाबालिग को पकड़ा

नई दिल्ली, वेब वार्ता

दिल्ली के सीलमपुर इलाके में 17 वर्षीय युवक की हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। थाना सीलमपुर और उत्तर-पूर्वी जिले की स्पेशल स्टाफ टीमों ने संयुक्त कार्रवाई में हत्या में शामिल दो किशोर आरोपियों को पकड़ लिया है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, 24 जून को रात करीब 9 बजे थाना सीलमपुर को गौतमपुरी की गली नंबर-4 में चाकूबाजी की घटना की सूचना मिली थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि घायल युवक को उसका चचेरा भाई इलाज के लिए जेपीसी अस्पताल ले गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान गौतमपुरी निवासी 17 वर्षीय लकी कुमार पुत्र रमेश के रूप में हुई। घटना की सूचना मिलने के बाद क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम ने मौके का निरीक्षण किया और महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। इसके आधार पर थाना सीलमपुर में एफआईआर संख्या 247/2026 के तहत धारा 103(1) बीएनएस में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। मामले की जांच के लिए थाना सीलमपुर के एसएचओ इंस्पेक्टर नरपाल सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें एसआई सुधांशु, हेड कांस्टेबल नवनीश, हेड कांस्टेबल मनीष फौजदार, कांस्टेबल विपिन और कांस्टेबल सचिन शामिल थे। यह टीम एसीपी सीलमपुर मल्कियत सिंह की निगरानी में कार्य कर रही थी। इसके अलावा, स्पेशल स्टाफ की एक टीम इंस्पेक्टर अरविंद के नेतृत्व में बनाई गई, जिसमें एसआई कौशिक घोष, एएसआई अमित त्यागी, एएसआई अमित मान, हेड कांस्टेबल मोनू कुमार और हेड कांस्टेबल आमिर शामिल थे। इस टीम की निगरानी एसीपी ऑपरेशंस सतेन्द्र सिंह कर रहे थे।

तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिये प्रयास किये जा रहे हैं

जांच के दौरान पुलिस टीमों ने विभिन्न स्रोतों से खुफिया जानकारी जुटाई और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का गहन विश्लेषण किया। तकनीकी साक्ष्यों और अन्य सुरागों के आधार पर संदिग्धों की पहचान की गई और उनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी की गई। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने हत्या में शामिल दो किशोर आरोपियों को पकड़ लिया। दोनों की उम्र लगभग 15 से 16 साल बताई गई है। दोनों ने वारदात में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली और अपने तीसरे साथी की पहचान भी उजागर की। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि घटना वाले दिन पहले उनका मृतक के साथ किसी मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद ने बाद में हिंसक रूप ले लिया और लकी कुमार पर जानलेवा हमला किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। वहीं, तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस मामले में आगे की जांच जारी है।

संक्षिप्त वार्ता

कोचिंग संस्थान में हुए भीषण अग्निकांड के बाद देवरिया जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क : मधुसूदन हुल्गी

वेब वार्ता, देवरिया

उत्तर प्रदेश के देवरिया में लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग संस्थान में हुए भीषण अग्निकांड के बाद देवरिया जिला प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क हो गया है। जनपद में कोचिंग सेंटरों, लाइब्रेरी, होटल, क्लिनिक एवं अस्पतालों की जांच अभियान चलाया जा रहा है।

इस संबंध में जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने बताया कि सभी संस्थानों में अग्निशमन व्यवस्था, आपातकालीन निकास (इमरजेंसी एग्जिट), भवन मानकों तथा अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं की गहन जांच कराई जा रही है। वही कई कोचिंग, लाइब्रेरी को सील किया गया हैं और कई लोगो को नोटिस के माध्यम से अवगत कराया गया हैं कि तत्काल फायर व्यवस्था में सुधार करा लें। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिन संस्थानों में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं पाया जाएगा। उनके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य किसी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकना और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

बाढ़ पूवार्नुमान और फ्लड प्लेन निर्धारण में मिलेगी मदद

वेब वार्ता, देवरिया

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में बाढ़ प्रबंधन के साथ नदियों के जलस्तर व प्रवाह की वैज्ञानिक निगरानी के लिए पूर्वांचल के तीन जिलों गोरखपुर, देवरिया व महराजगंज में पांच नई गेज–डिस्चार्ज साइटों की स्थापना को शासन ने स्वीकृति दे दी है। जिले में छोटी गंडक नदी पर पटनवा पुल के पास नई गेज–डिस्चार्ज साइट स्थापित की जाएगी। पांचों परियोजना के लिए शासन ने चार करोड़, 48 लाख, 88 हजार लाख रुपये की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में 150.12 लाख रुपये अवमुक्त किए हैं। छोटी गंडक नदी देवरिया, सलेमपुर व भाटपाररानी तहसील क्षेत्रों के अनेक गांवों से होकर गुजरती है। वर्तमान में जिले में सलेमपुर क्षेत्र के नदावर घाट पर ही गेज–डिस्चार्ज स्टेशन स्थापित है। ऐसे में नदी के विभिन्न हिस्सों के जलस्तर व प्रवाह संबंधी आंकड़ों के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाती है। इसे देखते हुए शासन ने पटनवा पुल के पास नई गेज–डिस्चार्ज साइट स्थापित करने का निर्णय लिया है।

देवरिया जिले में सड़क दुर्घटना में राहुल सिंह की गोरखपुर एम्स में उपचार के दौरान मौत

वेब वार्ता, देवरिया

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम गौरी खुर्द के समीप बुधवार को हुई सड़क दुर्घटना में घायल एक युवक की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार जिले के गौरीबाजार थाना क्षेत्र के पथरहट निवासी रोशन सिंह (40) पुत्र विजय प्रताप सिंह तथा सांडा गांव निवासी राहुल सिंह उर्फ बबलू (38) पुत्र सुरेंद्र सिंह बुधवार को बाइक से गोरखपुर जा रहे थे। बताया जाता है कि किसी कार्यवश गौरी खुर्द कट के पास उन्होंने बाइक मोड़ने का प्रयास किया। इसी दौरान गोरखपुर की ओर से तेज गति से आ रही एक स्कार्पियो ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल राहुल सिंह को एम्स गोरखपुर रेफर किया गया। जहां देर रात उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं रोशन सिंह का उपचार गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। इस संबंध में गौरी बाजार थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

कारोबार में घाटा हुआ तो हज यात्रा के नाम पर ठगी करने लगा

नोएडा। नोएडा साइबर थाना पुलिस ने मंगलवार शाम ग्रेटर नोएडा वेस्ट से एक ठग को गिरफ्तार किया। वह देश के विभिन्न राज्यों में बैठे लोगों को हज पर जाने का सस्ता पैकेज देने का झांसा देकर ठगी करता था। आरोपी अब तक पीड़ितों से करीब 46 लाख रुपये से अधिक की ठगी कर चुका है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सूचना मिली थी कि देश के विभिन्न राज्यों के लोगों को हज और उमरा पर भेजने के नाम पर सस्ते पैकेज देने का झांसा देकर धोखाधड़ी की जा रही है। ठगी करने वाले आरोपी के मोबाइल नंबरों की लोकेशन ग्रेटर नोएडा वेस्ट में दर्ज की जा रही है। तकनीकी सूचना के आधार पर पता चला कि यह मोबाइल नंबर कई डिवाइस में चलाए जा रहे हैं। लोकेशन के आधार पर साइबर थाने में तैनात निरीक्षक राजकुमार चंदेल के नेतृत्व में टीम मंगलवार रात करीब 11 बजे ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गोल्डन आई टेक जोन–4 में पहुंची। टीम ने लोकेशन के आधार पर छापेमारी की। मौके पर एक व्यक्ति मिला। उसकी पहचान जिला बरेली के बारादरी निवासी तसलीम साद के रूप में हुई। 35 साल के तसलीम ने बीटेक कर रखी है।

अलीगंज अग्निकांड में दिवंगत छात्रों को श्रद्धांजलि के निकला शांति मार्च

लखनऊ,वेबवार्ता

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते दिनों अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड में दिवंगत होने वाले छात्र- छात्राओं को गुरुवार आलमबाग गुरुद्वारा की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई और एक शांति मार्च निकाला गया। यह मार्च गुरुद्वारा आलमबाग से प्रारंभ होकर रामनगर, आलमबाग क्रॉसिंग होते हुए पुनः गुरुद्वारा साहिब पहुंचा। शांति मार्च में शामिल संगत ने दिवंगत छात्र -छात्राओं की आत्माओं की शांति एवं उनके परिजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए अरदास की गई। इस अवसर पर दशमेश पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल सरबजीत कौर एवं विद्यालय के शिक्षकगण भी शांति मार्च में शामिल हुए।

पीलीभीत में शुरू होगी लेपर्ड सफारी

लखनऊ में बनेगा स्नैक वेनम एक्सट्रैक्शन सेंटर

लखनऊ, वेब वार्ता। प्रदेश के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने गुरुवार को बापू भवन स्थित कार्यालय कक्ष में पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा नेशनल पार्क, इटावा लायन सफारी, कानपुर प्राणी उद्यान एवं नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, लखनऊ की प्रगति एवं कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में वन्यजीव संरक्षण, पर्यटक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण तथा इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

डॉ. सक्सेना ने कहा की जनपद पीलीभीत में लेपर्ड की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए वहां शीघ्र ही एक अत्याधुनिक लेपर्ड सफारी विकसित की जाएगी। इसके लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार कर लिया गया है तथा परियोजना को जल्द धरातल पर उतारने के निर्देश दिए गए हैं।

शीघ्र पूर्ण करने के दिये निर्देश

यह सफारी प्रदेश में वन्यजीव पर्यटन को नई पहचान देने के साथ-साथ पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण केंद्र बनेगी। इटावा लायन सफारी की समीक्षा के दौरान वहां की आधारभूत सुविधाओं एवं लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

जनहित से जुड़े कार्यों को मिल सके नई गति

कहा गया कि सफारी में आने वाले पर्यटकों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित की जाएं। बैठक में लखनऊ में स्नैक वेनम एक्सट्रैक्शन सेंटर की स्थापना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। निर्देश दिए गए कि इस महत्वपूर्ण परियोजना को जल्द से जल्द मूर्त रूप दिया जाए, जिससे सर्पदंश उपचार, विष अनुसंधान तथा जनहित से जुड़े कार्यों को नई गति मिल सके।

आंगतुकों की संख्या में हो निरंतर वृद्धि

सभी चिड़ियाघरों के निदेशकों को निर्देशित किया गया कि प्राणी उद्यानों में वन्यजीवों की उपलब्धता, स्वास्थ्य एवं संरक्षण संबंधी व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नवीन गतिविधियों, सुविधाओं और जन-जागरूकता कार्यक्रमों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आगंतुकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो। बैठक में वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन तथा प्रदेश में पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चल रही योजनाओं एवं परियोजनाओं की प्रगति की भी विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में प्रमुख सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन वी हेकाली झिमोमी, पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ अनुराधा बेमूरी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

एमजीयूजी के कृषि संकाय के 13 विद्यार्थियों का कैंपस प्लेसमेंट

गोरखपुर, वेब वार्ता। महोयोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर (एमजीयूजी) के कृषि संकाय के 13 विद्यार्थियों का कैंपस प्लेसमेंट कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की कंपनी एकेएसवी खेत खलिहान क्रॉप प्राइवेट लिमिटेड में हुआ है। चयनित विद्यार्थियों ने इस उपलब्धि का श्रेय संकाय सदस्यों के मार्गदर्शन तथा विश्वविद्यालय के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण को दिया है।

कुलपति डॉ. सुरिंदर सिंह व कुलसचिव डॉ. प्रदीप कुमार राव ने इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए चयनित विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई दी तथा उनके सफल एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। उन्होंने कहा कि यह सफलता महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कृषि संकाय के समस्त प्राध्यापकों के अध्यापन, उत्कृष्ट प्रशिक्षण व्यवस्था तथा विद्यार्थियों के समग्र विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। कैंपस प्लेसमेंट हासिल करने वाले विद्यार्थियों रीतू पांडेय, आशुतोष, रितिका, मान, प्रियम्बदा, प्रिया सिंह, शिवानी, विवेक पटेल, अग्रज साहनी, शालू, उर्वशी सिंह, प्रियेश राम और पुष्पा को बधाई देते हुए कृषि संकाय के अधिष्ठाता डॉ. विमल कुमार दुबे ने कहा कि संकाय का लक्ष्य विद्यार्थियों को केवल रोजगार के लिए तैयार करना नहीं, बल्कि उन्हें कृषि क्षेत्र में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने हेतु सक्षम बनाना है।

बीएचयू विज्ञान संस्थान में एमएससी लाइफ साइंसेज पर नया पाठ्यक्रम, प्रवेश पंजीकरण शुरू

वाराणसी, वेब वार्ता। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के विज्ञान संस्थान जैव प्रौद्योगिकी विभाग के इंटरडिसिप्लिनरी स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज के नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सत्र 2026–27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) के सहयोग से स्थापित इंटरडिसिप्लिनरी स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज एक बहुविषयक एवं शोध–उन्मुख कार्यक्रम है, जिसमें वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, जैव रसायन, जैव प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान तथा कम्प्यूटेशनल जीव विज्ञान जैसे विषयों का समन्वित अध्ययन कराया जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को जीवन विज्ञान की जटिलताओं की समग्र समझ प्रदान करना तथा स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण एवं जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित समकालीन चुनौतियों के समाधान हेतु सक्षम बनाना है। बीएचयू जनसम्पर्क कार्यालय के अनुसार दो वर्षीय (चार सेमेस्टर) के इस कार्यक्रम में उन्नत प्रयोगशाला प्रशिक्षण, अनुसंधान पद्धति, जैव–सूचना विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जैविक अनुप्रयोग, फील्ड अध्ययन तथा शोध–आधारित प्रबंध को विशेष महत्व दिया गया है। विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में प्रवेश कट पीजी में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। विश्वविद्यालय के नियमानुसार काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से सीट आवंटन किया जाएगा।

घर के बंद कमरे में मिला अधेड़ का सड़ा शव, बेटे ने पिता मानने से किया इनकार

औरैया, वेब वार्ता। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में दिबियापुर थाना क्षेत्र के ककोर बुजुर्ग गांव में एक अधेड़ व्यक्ति का सड़ा-गला शव बीती रात बुधवार को उसके घर के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। शव करीब दो से तीन दिन पुराना बताया जा रहा है। घर से तेज दुर्गंध आने पर पड़ोसियों और परिजनों को घटना की सूचना पुलिस को दी थी। जानकारी के अनुसार, ककोर बुजुर्ग निवासी अरविंद तिवारी (५०)पुत्र शरद तिवारी अपने घर में अकेले रहते थे। वह एक सिक्योरिटी ऑफिस में कार्यरत थे। बुधवार रात करीब 10 बजे उनके भतीजे अभिषेक ने घर से तेज बदबू आने पर कमरे में जाकर देखा तो चाचा अरविंद का शव पड़ा मिला। उसने तत्काल पुलिस को सूचना दी।

कछौना में भाकियू लोकतांत्रिक का प्रदर्शन

ज्ञापन लेने नहीं पहुंचा कोई अधिकारी, किसानों में रोष

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के बैनर तले गुरुवार को प्रदेश प्रभारी उमेश शुक्ला के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों, महिलाओं और पदाधिकारियों ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, विकास कार्यों में लापरवाही, खाद की किल्लत और पेयजल संकट जैसे मुद्दों पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया।

प्रदर्शनकारी किसान लंगड़े दास बाबा कुटी प्रांगण में देर शाम तक डटे रहे, लेकिन उनका आरोप है कि प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं पहुंचा। इससे किसानों में नाराजगी और आक्रोश देखने को मिला।

बैठक के दौरान किसानों ने कछौना कोतवाली पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि जिले में ईमानदार पुलिस अधीक्षक होने के बावजूद स्थानीय स्तर पर पुलिस की कार्यप्रणाली में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। किसानों का कहना था कि बीट सिपाहियों द्वारा वसूली की शिकायतें लगातार मिल रही हैं, जबकि चोरी, अवैध पेड़ कटान और कच्ची शराब की बिक्री जैसी घटनाओं पर प्रभावी अंकुश नहीं लग पा रहा है। किसानों ने जल जीवन मिशन के कार्यों में भी अनियमितताओं का आरोप लगाया। उनका कहना है कि कई गांवों में अभी तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुचारु नहीं हो सकी है। पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत नहीं कराई गई है, वहीं टूटी टोटियों और पाइपलाइन लीकेज के कारण पानी की बबार्दी हो रही है। खाद संकट का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया।

किसानों ने बताया कि क्षेत्र की साधन सहकारी समितियों पर पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं है। चार समितियों के संचालन के लिए मात्र दो सचिव तैनात होने के कारण समितियां नियमित रूप से नहीं खुल पा रही हैं। स्टेशन पार स्थित पीसीएफ केंद्र कई वर्षों से बंद पड़ा है, जिससे किसानों को बाजार से ऊंचे दामों पर खाद खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने औद्योगिक क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने, ग्राम सभाओं में सफाई कर्मियों की नियमित तैनाती सुनिश्चित करने तथा क्षेत्रीय समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की।

परीक्षाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप सकुशल, निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराए: दीपक कुमार

लखनऊ, वेब वार्ता। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) 2026 की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार ने गुरुवार को करते हुए संबंधित मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए।

कृषि उत्पादन आयुक्त ने निर्देशित किया कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन निर्धारित मानकों के अनुरूप सकुशल, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित ढंग से सुनिश्चित किया जाए। परीक्षा सामग्री की सुरक्षा से लेकर परीक्षा केंद्रों की निगरानी तक प्रत्येक स्तर पर विशेष सतर्कता बरती जाए।अभ्यर्थियों की चेकिंग एवं फ्रिस्किंग पूरी गंभीरता के साथ की जाए। उन्होंने कहा कि गोपनीय परीक्षा सामग्री का भंडारण कोषागार के डबल–लॉक सिस्टम में किया जाए

तथा प्रश्नपत्रों एवं अन्य गोपनीय सामग्री का परिवहन सेक्टर मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा में सुनिश्चित किया जाए। परीक्षा केंद्रों पर स्थापित कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से सतत निगरानी रखी जाए। कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि प्रश्नपत्रों को खोलने, वितरण करने तथा परीक्षा समाप्ति के उपरांत पुनः सील करने की संपूर्ण प्रक्रिया निर्धारित मानकों के अनुरूप संपन्न कराई जाए। इसके लिए परीक्षा से संबंधित सभी कार्मिकों को पूर्व में ही संवेदनशील एवं प्रशिक्षित किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि की संभावना न रहे। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि संपूर्ण प्रक्रिया की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी कराई जाए, जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना समाप्त हो सके। साथ ही, निरीक्षकों का कक्ष आवंटन स्टेटिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाए, मोबाइल फोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहे, सभी संबंधित कार्मिकों से ह्यनो रिलेशन सर्टिफिकेटह्न प्राप्त किया जाए तथा परीक्षा सामग्री की पैकिंग एवं सीलिंग में निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि यातायात प्रबंध, चिकित्सकीय प्रबंध, पेयजल की उपलब्धता एवं सुचारू विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की जाए।

पात्रों को समयबद्ध रूप से ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें : जिलाधिकारी

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। जनपद में रोजगार सृजन एवं आर्थिक गतिविधियों को गति देने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अनुनय झा की अध्यक्षता में स्वामी विवेकानंद सभागार में जिला परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बैंकिंग गतिविधियों, विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत ऋण वितरण तथा वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने सभी बैंक शाखाओं को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मुद्रा योजना समेत अन्य स्वरोजगारपरक योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध रूप से ऋण उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि बैंक और संबंधित विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर जनपद में रोजगार के नए अवसर सृजित करें तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दें।

बैठक में विभिन्न बैंकों के जमा-ऋण अनुपात, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण वितरण, कृषि ऋण, स्वयं सहायता समूहों के वित्तपोषण एवं वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। लक्ष्य के अनुरूप प्रगति न करने वाले बैंक अधिकारियों को जिलाधिकारी ने आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए।

अग्रणी जिला प्रबंधक अरविंद रंजन ने जनपद की बैंकिंग स्थिति एवं विभिन्न योजनाओं की उपलब्धियों का प्रस्तुतीकरण करते हुए बताया कि बैंक सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सक्रिय सहयोग प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी।

किसान क्रेडिट कार्ड बनाने दिये निर्देश

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने मछुआ समुदाय के पात्र लोगों के किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) बनाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला ऋण योजना का विमोचन भी किया। इस अवसर पर जिला उद्योग अधिकारी हर्ष प्रताप सिंह, अग्रणी जिला प्रबंधक अरविंद रंजन, जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी, विभिन्न बैंक शाखाओं के अधिकारी, जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

पत्नी की बेवफाई से आहत पति ने ट्रक के आगे कूदकर दी जान, थाने में चलती रही पंचायत

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। रिश्तों की डोर जब विश्वास के सहारे बंधी हो और वही विश्वास टूट जाए, तो उसका दर्द कितना गहरा हो सकता है, इसका दर्दनाक उदाहरण बुधवार को माधौगंज थाना क्षेत्र में देखने को मिला। थाने के भीतर पति-पत्नी के विवाद को सुलझाने के प्रयास चल रहे थे, लेकिन बाहर एक युवक अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई हार चुका था। कुछ ही पलों बाद उसने ऐसा कदम उठा लिया, जिसने पूरे परिवार को मातम में डुबो दिया।

माधौगंज थाना क्षेत्र के ग्राम लखनपुर निवासी चंद्र प्रकाश अपनी पत्नी के साथ पंजाब के लुधियाना में रहकर मेहनत-मजदूरी करता था। छोटी-सी गृहस्थी थी, सपने थे, परिवार था और एक मासूम बेटा था, जिसके भविष्य को संवारने के लिए वह दिन-रात मेहनत करता था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था।

पुलिस जांच के अनुसार लुधियाना में रहने के दौरान चंद्र प्रकाश के रिश्तेदार राहुल और उसकी पत्नी के बीच प्रेम प्रसंग हो गया। जब इसकी जानकारी चंद्र प्रकाश को हुई तो वह पत्नी को लेकर अपने गांव लौट आया। मामला बढ़ा तो पत्नी ने राहुल के खिलाफ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए माधौगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया। बुधवार को इसी मामले को लेकर दोनों पक्ष थाने में मौजूद थे। पुलिस की मौजूदगी में बातचीत और बयान की प्रक्रिया चल रही थी। तभी घटनाक्रम ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पुलिस के अनुसार महिला ने अपने पति के साथ जाने से इनकार कर दिया और राहुल के साथ रहने की इच्छा जताई।

पत्नी के मुंह से यह बात सुनकर चंद्र प्रकाश भीतर तक टूट गया। जिस रिश्ते को बचाने की उम्मीद लेकर वह थाने पहुंचा था, उसी रिश्ते के बिखरने की घोषणा उसके सामने हो गई। वर्षों का विश्वास, साथ जीने-मरने के वादे और परिवार को बचाने की सारी उम्मीदें एक पल में चकनाचूर हो गईं।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ देर बाद चंद्र प्रकाश थाने के बाहर पहुंचा और सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक के आगे कूद गया। देखते ही देखते मौके पर चीख-पुकार मच गई। लोग दौड़े, पुलिसकर्मी भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गंभीर रूप से घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माधौगंज ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

इस एक घटना ने कई जिंदगियों को बदल दिया। वृद्ध मां के बुढ़ापे का सहारा छिन गया। भाइयों और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। सबसे मार्मिक तस्वीर उस मासूम बेटे की है, जिसे शायद अभी यह भी नहीं मालूम कि उसके सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ चुका है।

क्षेत्राधिकारी बिलग्राम राम सूरत सोनकर ने बताया कि जांच में यह तथ्य सामने आया है कि मृतक की पत्नी और उसके रिश्तेदार राहुल के बीच प्रेम प्रसंग था। पत्नी द्वारा पति के साथ जाने से इनकार किए जाने से आहत होकर युवक ने ट्रक के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है तथा मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

माधौगंज की यह घटना केवल एक आत्महत्या की कहानी नहीं है, बल्कि टूटते रिश्तों, बिखरते विश्वास और एक परिवार के दर्दनाक अंत की कहानी है। थाने में पंचायत चलती रही, समाधान तलाशे जाते रहे, लेकिन उसी दौरान एक घर का चिराग बुझ गया, एक मां की दुनिया उजड़ गई और एक मासूम की जिंदगी से पिता का साया हमेशा के लिए छिन गया।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बागियों की सांसदी पर जल्द लेंगे फैसला

दो-तिहाई बहुमत का नियम अहम

नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जल्द ही तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और शिवसेना (यूबीटी) के बागी सांसदों के दल-बदल मामले में अपना महत्वपूर्ण फैसला सुना सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र से पहले स्पीकर इस पर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, जिसका भारतीय राजनीति पर गहरा असर पड़ सकता है। स्पीकर ने दोनों मूल पार्टियों और उनके बागी गुटों के प्रतिनिधिमंडलों से पहले ही मुलाकात कर ली है ताकि सभी पक्षों को सुना जा सके। संसद से जुड़े कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञ इस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लिया गया निर्णय कानूनी रूप से पूरी तरह सही हो, दल-बदल विरोधी कानून से जुड़े पुराने मामलों और मिसालों की भी गहन समीक्षा की जा रही है।

टीएमसी के मामले में, पार्टी ने 2024 के आम चुनाव में लोकसभा की 29 सीटें जीती थीं, जिनमें से एक सांसद के निधन के बाद फिलहाल एक सीट खाली है। पार्टी के 20 सांसदों ने बगावत करते हुए पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्थित एक रजिस्टर्ड लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) का दामन थाम लिया है। इन बागियों ने लोकसभा में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की है। इसके साथ ही इन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को अपना समर्थन जताते हुए एनडीए में शामिल होने की इच्छा भी जाहिर की है। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पार्टी के बागी गुट के साथ स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा है। बनर्जी ने इन 20 बागियों को अयोग्य ठहराने के लिए स्पीकर को अलग-अलग याचिकाएं भी सौंपी हैं, जिसमें दल-बदल विरोधी कानून के उल्लंघन का हवाला दिया गया है।

महाराष्ट्र में शिवसेना (यूबीटी) के मामले में भी ऐसी ही स्थिति है। शिवसेना (यूबीटी) के टिकट पर 9 सांसद चुने गए थे, जिनमें से 6 सांसद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं। बुधवार को शिवसेना (यूबीटी) के नेता अनिल देसाई और अरविंद सावंत ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और संविधान के प्रावधानों को बनाए रखने की अपील की। उद्धव गुट के नेताओं ने स्पीकर से शिंदे गुट में शामिल होने वाले 6 बागी सांसदों द्वारा दिए गए किसी भी लिखित ज्ञापन की कॉपी मांगी। इस पर स्पीकर ने उन्हें बताया कि बागी सांसदों की तरफ से अभी तक उन्हें लिखित में कुछ भी नहीं मिला है। टीएमसी और शिवसेना (यूबीटी) दोनों ने स्पीकर से दल-बदल विरोधी कानून के तहत अपने बागी सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। दोनों पार्टियों का तर्क है कि दल-बदल कानून के तहत अयोग्यता से संरक्षण केवल तभी मिलता है, जब पूरी राजनीतिक पार्टी के कम से कम दो-तिहाई हिस्से का किसी दूसरी पार्टी में विलय हो, न कि केवल विधायकों या सांसदों के एक समूह का।

...बदलाव ला सकती है

अभिषेक बनर्जी ने स्पष्ट किया कि केवल विधायकों या सांसदों के एक समूह के विलय को कानूनी रूप से मान्यता नहीं दी जा सकती। वहीं अनिल देसाई ने भी जोर देकर कहा कि 10वीं अनुसूची बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी विधायक दल का कोई समूह अपने आप किसी दूसरी पार्टी में विलय नहीं कर सकता, भले ही उनके पास दो-तिहाई बहुमत ही क्यों ना हो। लोकसभा सचिवालय आगामी मॉनसून सत्र के लिए सांसदों के बैठने की नई व्यवस्थाओं का आकलन कर रहा है। टीएमसी और शिवसेना (यूबीटी) के बागी गुटों के अलावा, डीएमके ने भी संसद में कांग्रेस से अलग बैठने की मांग की है। दरअसल, डीएमके ने कांग्रेस के साथ अपना पुराना गठबंधन खत्म कर लिया है और अब मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके के साथ गठबंधन कर लिया है। यह स्थिति संसद के भीतर राजनीतिक समीकरणों और बैठने की व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है।

मॉनसूनः कहीं मूसलाधार बारिश, कहीं आंधी-तूफान, 14 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट

नई दिल्ली। भारत इस समय मौसम के कई अलग-अलग रूपों का सामना कर रहा है। एक ओर जहां दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून बेहद मजबूत स्थिति में तेजी से आगे बढ़ रहा है और देश के एक बड़े हिस्से को भिगो रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ इलाकों में आंधी-तूफान और गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल रही हैं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश के 14 राज्यों के लिए आज यानी 25 जून को भारी से बहुत भारी बारिश और गंभीर स्तर के आंधी-तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग प्रभावों का संकेत देता है।मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन के अनुसार, दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून की उत्तरी सीमा इस समय दहानू, वर्धा, रायपुर, डालटनगंज और मोतिहारी से होकर गुजर रही है। पिछले 24 घंटों में मॉनसून ने महाराष्ट्र के बचे हुए हिस्सों को पूरी तरह कवर कर लिया है और गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व झारखंड के नए इलाकों में भी अपनी दस्तक दे दी है, जिससे इन राज्यों में भी बारिश का दौर शुरू हो गया है।

मध्य और पूर्वी भारत में मौसम का हाल

बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ और ओडिशा में गंभीर चेतावनी आज के मौसम की सबसे गंभीर चेतावनी मध्य और पूर्वी भारत के राज्यों के लिए है, जहां मध्यम से गंभीर स्तर की आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं।बिहार में आज मौसम काफी आक्रामक हो सकता है, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली विनाशकारी हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान है। झारखंड में गरज-चमक के साथ तेज बौछारें पड़ेंगी।जबकि मध्य प्रदेश के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय है, जिसके प्रभाव से पश्चिमी मध्य प्रदेश में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जबकि विदर्भ (महाराष्ट्र) और पूर्वी मध्य प्रदेश में गरज-चमक के साथ लगातार भारी बारिश जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल (उप-हिमालयी) और सिक्किम में मॉनसून बहुत ज्यादा सक्रिय है, यहां आने वाले 2-3 दिनों तक मूसलाधार बारिश का दौर चलता रहेगा। ओडिशा में आज रात तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उप्र

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए आज का दिन राहत और थोड़ी आफत दोनों लेकर आया है। राजस्थान के ऊपर बने एक चक्रवातीय सिस्टम के कारण पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने की आशंका है, जिसका सीधा असर दिल्ली-एनसीआर और पंजाब-हरियाणा पर दिखेगा। आज इन इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा (झोंकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक) की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाएं या थंडरस्कॉल आ सकते हैं। आंधी के साथ ही गरज-चमक और मध्यम स्तर की बारिश होगी, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि, आईएमडी ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे आंधी के समय खुली जगहों या पेड़ों के नीचे जाने से बचें।

पश्चिमी तट और दक्षिण भारत

मुंबई, कोंकण, गोवा और कर्नाटक में मॉनसून का कहर पश्चिमी तट और दक्षिण भारत के राज्य इस समय मॉनसून की सबसे भारी मार झेल रहे हैं। मुंबई, उत्तरी कोंकण और गोवा में पिछले दिनों मुंबई और आसपास के इलाकों में हुई बहुत ज्यादा भारी बारिश के बाद आज भी राहत के आसार नहीं हैं। मुंबई सहित पूरे नॉर्थ कोंकण और गोवा में आज भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। लगातार हो रही बारिश के कारण मुंबई के निचले इलाकों में जलभराव और लोकल ट्रांसपोर्ट/यातायात प्रभावित होने की पूरी आशंका है। कर्नाटक के समुद्र की तरफ से आ रही तेज हवाओं के कारण मॉनसून सबसे ज्यादा उग्र रूप में है, यहां मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और मराठवाड़ा क्षेत्रों में भी मॉनसूनी बारिश आज भी जारी रहेगी।

पूर्वोत्तर भारतः असम, अरुणाचल और मेघालय में बाढ़-भूस्खलन का खतरा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मॉनसूनी हवाएं एक जगह ठहर सी गई हैं, जिससे यहां लगातार होने वाली भारी बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 27 और 28 जून को उप-हिमालयी क्षेत्रों में 21 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश दर्ज की जा सकती है, जिससे पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है और असम के मैदानी इलाकों में बाढ़ का जोखिम भी बढ़ गया है।लू और गर्म रातों का दौर, जल्द राहत की उम्मीद एक तरफ जहां देश के तीन-चौथाई हिस्से में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी है, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम का बिल्कुल उलट रूप दिख रहा है। राहत की बात यह है कि अगले 48 से 72 घंटों के भीतर मॉनसून तेजी से आगे बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश के बचे हुए हिस्सों के साथ-साथ उत्तराखंड को भी पूरी तरह कवर कर लेगा, जिसके बाद जून के आखिरी वीकेंड तक यहां भी मॉनसून की पहली जोरदार बारिश होगी, जिससे लोगों को गर्मी से निजात मिलेगी।

गॉडजिला अल नीनो से भारत सहित दक्षिण एशिया पर सूखे-बाढ़ का खतरा

नई दिल्ली। भारत सहित दक्षिण एशिया के कई देशों पर सूखे और बाढ़ का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसका कारण अल नीनो की मजबूत होती स्थिति है, इस विशेषज्ञ 1997 के गॉडजिला अल नीनो से जोड़ रहे हैं, जो इतिहास का सबसे शक्तिशाली अल नीनो था। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी (जेपीएल) के अनुसार, पश्चिमी प्रशांत महासागर में वैसी ही परिस्थितियाँ बन रही हैं, और यह पिछले कुछ दशकों का सबसे प्रभावशाली अल नीनो साबित हो सकता है। नासा के उपग्रहों ने समुद्र में जमा हो रही भारी मात्रा में गर्मी के चौंकाने वाले आंकड़े और तस्वीरें जारी की हैं।

सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलिच सैटेलाइट से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर के बड़े हिस्से में समुद्र का जलस्तर सामान्य से काफी अधिक है। यह इसका स्पष्ट संकेत है कि समुद्र की सतह के नीचे बड़ी मात्रा में गर्म पानी जमा हो रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब समुद्र का पानी गर्म होता है तब वह फैलता है, जिससे जलस्तर बढ़ जाता है। समुद्र की सतह के नीचे जमा यह गर्मी दुनिया भर के मौसम को गहराई से प्रभावित करती है। यदि गर्म पानी का यह भंडार बड़ा और गहरा हो जाए, तब इसका वैश्विक असर होता है, जिससे कई देशों में मौसम का संतुलन बिगड़ सकता है। समुद्र के भीतर केल्विन वेव्स नाम की विशाल जल-तरंगें इस गर्मी को प्रशांत महासागर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा रही हैं। जब प्रशांत महासागर की व्यापारिक हवाएं कमजोर पड़ती हैं, तब इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पास जमा गर्म पानी पूर्व की ओर, दक्षिण अमेरिका के तटों की तरफ बढ़ने लगता है। इस प्रक्रिया से समुद्र की गहराई से ऊपर आने वाला ठंडा पानी कम हो जाता है और समुद्र का तापमान तेजी से बढ़ने लगता है, जो अल नीनो की एक प्रमुख पहचान है। हालांकि पूर्वी प्रशांत महासागर अभी 1997 जितना गर्म नहीं हुआ है, नई केल्विन वेव्स लगातार उस क्षेत्र की ओर बढ़ रही हैं, जिससे अल नीनो के आने वाले महीनों में और मजबूत होने के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। इतिहास गवाह है कि अल नीनो के दौरान दुनिया के कई हिस्सों में अत्यधिक बारिश और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और एशिया जैसे क्षेत्रों में भीषण सूखे की स्थिति बन सकती है। अमेरिका की राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन (एनओएए) ने 11 जून को ही अल नीनो की स्थिति घोषित कर दी थी।

कुरनूल की जोन्नागिरी खदान से शुरू होगा सोना उत्पादन

हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के खनन इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ने जा रहा है, क्योंकि कुरनूल जिले की जोन्नागिरी खदान में व्यावसायिक स्तर पर सोने का उत्पादन शुरू होने वाला है। लगभग बीस साल के लंबे इंतजार और विस्तृत नियोजन के बाद राज्य की मिट्टी से सोना निकालने का सपना अब साकार होने जा रहा है।

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू तुग्गली मंडल में स्थित इस गोल्ड प्रोसेसिंग प्लांट का औपचारिक उद्घाटन करेंगे और साथ ही इसी क्षेत्र में सोने के अयस्क की रिफाइनिंग की दूसरी यूनिट की आधारशिला भी रखेंगे, जो राज्य के लिए एक स्वर्ण युग की शुरूआत का प्रतीक है।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना से प्रारंभिक चरण में प्रतिदिन लगभग एक किलोग्राम सोने का उत्पादन होने की उम्मीद है, जिसका लक्ष्य धीरे-धीरे सालाना 600 किलोग्राम तक बढ़ाना है। अंतिम रूप से, इस खदान का उद्देश्य प्रति वर्ष 1,500 किलोग्राम सोने का उत्पादन करना है, जिसके लिए सालाना 4 लाख टन अयस्क खनन की योजना है। जोन्नागिरी खदान में परीक्षण उत्पादन पहले ही सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, और अब उत्पादन क्षमता को और बढ़ाने के लिए जोन्नागिरी के आसपास 1,200 एकड़ में खनन गतिविधियों का विस्तार किया जाएगा। जोन्नागिरी क्षेत्र में सोने के विशाल भंडार की पहचान काफी दिलचस्प तरीके से हुई थी। दशकों पहले, इस इलाके में अक्सर हीरे मिलने की खबरों के बाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने विस्तृत सर्वेक्षण शुरू किया था। लगभग तीन दशकों तक चले व्यापक भूवैज्ञानिक अध्ययन के बाद, जोन्नागिरी, एरागुडी और पगिरिडायी गांवों में व्यावसायिक रूप से सोने की उपलब्धता की पुष्टि हुई। इस खोज के बाद, साल 2006 में जियोमायसोर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 1,477.24 एकड़ क्षेत्र में खनन अधिकार हासिल किए। कंपनी ने अत्याधुनिक गोल्ड प्रोसेसिंग सुविधा स्थापित करने के लिए 320 करोड़ रुपये का भारी निवेश किया है, जिससे लगभग 800 कर्मचारियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। अधिकारियों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में प्रशासनिक बाधाओं के कारण इस परियोजना में काफी देरी हुई थी।

हालांकि, मौजूदा गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद लंबित मंजूरियों और बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यों में तेजी लाई गई, जिससे यह परियोजना अंततः उत्पादन के चरण तक पहुंच पाई। सर्वेक्षणों से अनुमान है कि इस क्षेत्र में एक करोड़ टन से अधिक सोने का अयस्क मौजूद है, जिसमें अकेले ईस्ट ब्लॉक में ही लगभग 68 लाख टन अयस्क दबा है। जमीन की सतह से 180 मीटर से लेकर लगभग 2 किलोमीटर नीचे तक सोने के अयस्क की पहचान की गई है, जो इसकी विशाल क्षमता को दशार्ता है। राज्य की स्वर्ण योजनाएं केवल जोन्नागिरी तक ही सीमित नहीं हैं।

उम्मीद है कि जल्द ही अनंतपुर जिले के रामगिरी क्षेत्र में भी सोने का उत्पादन शुरू होगा, और चित्तूर जिले में भी सोने के भंडार की पहचान की गई है। पाइपलाइन में मौजूद इन कई परियोजनाओं के साथ, आंध्र प्रदेश आने वाले वर्षों में भारत के प्रमुख सोना उत्पादक राज्यों में से एक बनने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को एक नई गति और समृद्धि मिलेगी।

राजधानी-शताब्दी में 2 घंटे की देरी पर मिलेगा मुफ्त भोजन!

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे हर दिन लाखों यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है, जो देश की जीवनरेखा मानी जाती है। हालांकि, खराब मौसम, तकनीकी खराबी, या अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियों की वजह से कई बार ट्रेनों में देरी भी हो जाती है। ऐसी स्थिति में यात्रियों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, जिससे उन्हें असुविधा और परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रेलवे ने कुछ प्रीमियम ट्रेनों के यात्रियों के लिए एक खास व्यवस्था की हुई है, जो ऐसे समय में उन्हें बड़ी राहत प्रदान करती है। अगर राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी चुनिंदा ट्रेनों में यात्रा के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक देरी होती है, तो यात्रियों को रेलवे की ओर से मुफ्त भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यह व्यवस्था यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने और उन्हें बेहतर यात्रा अनुभव देने के उद्देश्य से बनाई गई है। रेलवे की कैटरिंग सर्विस संभालने वाली आईआरसीटीसी के नियमों के अनुसार, यदि राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनों में कोई ट्रेन अपने निर्धारित समय से 2 घंटे या उससे ज्यादा देर से चल रही हो, तो यात्रियों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

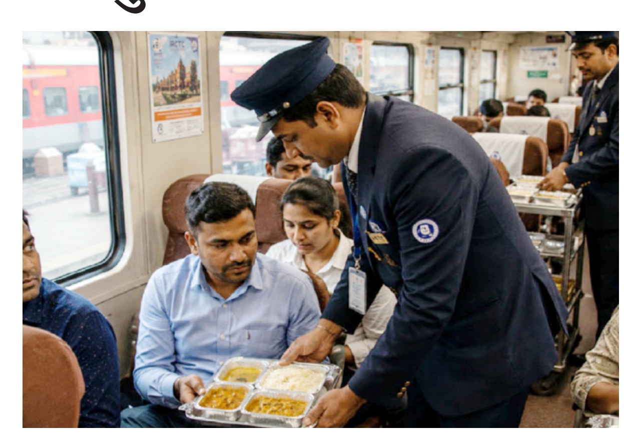

यह सुविधा सुनिश्चित करती है कि लंबी देरी के कारण यात्रियों को भूखा न रहना पड़े। यात्रा के समय और देरी की अवधि के अनुसार, यात्रियों को चाय, कॉफी, बिस्किट, ब्रेड-बटर और अन्य हल्के नाश्ते दिए जा सकते हैं। यदि देरी भोजन के समय तक जारी रहती है, तो यात्रियों को लंच या डिनर भी उपलब्ध कराया जाता है। आमतौर पर, इस भोजन में चावल, दाल, सब्जी, रोटी या पूरी और अन्य जरूरी खाने की सामग्री शामिल होती है, ताकि यात्रियों को एक पौष्टिक आहार मिल सके। यह सुविधा मुख्य रूप से उन ट्रेनों में लागू होती है जहां टिकट के साथ भोजन पहले से ही शामिल होता है।

3 घंटे से अधिक की देरी पर टिकट रद्द करने की सुविधा

इसके अतिरिक्त, रेलवे के नियमों में लंबी देरी की स्थिति में टिकट रिफंड का भी प्रावधान है। अगर किसी ट्रेन के प्रस्थान में 3 घंटे या उससे अधिक की देरी होती है, तो यात्री अपना टिकट रद्द कराकर पूरे किराए की वापसी पाने के हकदार हो सकते हैं। यह सुविधा उन यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत है जो लंबी देरी के कारण अपनी यात्रा नहीं करना चाहते या जिनके लिए देरी से यात्रा करना संभव नहीं होता। ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों को निर्धारित नियमों के तहत रिफंड प्रक्रिया पूरी करनी होती है, जबकि काउंटर से टिकट खरीदने वाले यात्रियों को रेलवे के नियमों के अनुसार टिकट रद्द कराना पड़ता है। हालांकि, रिफंड के नियम टिकट के प्रकार और परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए यात्रियों को हमेशा नवीनतम जानकारी के लिए रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या पूछताछ काउंटर से संपर्क करना चाहिए। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा पर लगातार ध्यान केंद्रित करता है। लंबी देरी की स्थिति में रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त इंतजाम भी किए जाते हैं।

संघर्ष विराम के बाद भी भारतीय नौसेना खाड़ी में अपनी तैनाती कम नहीं करेगी

नई दिल्ली। ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष विराम होने के बावजूद भारतीय नौसेना ने खाड़ी क्षेत्र में अपनी तैनाती कम नहीं करेगी। नौसेना अपने पूर्व संघर्ष स्तर पर ही युद्धपोतों, हेलिकॉप्टरों और मार्कोस कमांडो की तैनाती बनाए रखेगी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा, तेल और एलपीजी का सुरक्षित परिवहन और समुद्री मार्गों की निगरानी करना है। ऑपरेशन संकल्प 2019 से लगातार चल रहा है, जो होर्मुज और अरब सागर के उत्तरी हिस्से में सुरक्षा सुनिश्चित करता है। हाल के ईरान-अमेरिका संघर्ष के दौरान नौसेना ने अपनी मौजूदगी और बढ़ा दी थी। अब संघर्ष विराम के बावजूद स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं मानी जा रही, इसलिए नौसेना तैनाती बनाए रखेगी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन संकल्प भारत की समुद्री सुरक्षा नीति का अहम हिस्सा है। इसके तहत भारतीय नौसेना खाड़ी ओमान और अदन की खाड़ी में नियमित गश्त करती है। युद्धपोत भारतीय ध्वज वाले मर्चेंट वेसल्स को जरूरत पड़ने पर एस्कॉर्ट करते हैं। हेलिकॉप्टर हवाई निगरानी करते हैं जबकि मार्कोस कमांडो अभियानों के लिए तैयार रहते हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। उसका बड़ा हिस्सा होर्मुज से गुजरता है। इस खाड़ी में कोई भी अस्थिरता भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सीधे प्रभावित करती है। इसलिए नौसेना ने 2019 से स्थाई रूप से युद्धपोत तैनात रखे हैं, जो हाल के संकट में और उपयोगी साबित हुए। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार और नौसेना का मानना है कि क्षेत्र में शांति स्थाई नहीं है, इसलिए सतर्कता बनाए रखना जरूरी है। यह फैसला भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और ऊर्जा सुरक्षा को दशार्ता है। चीन की बढ़ती नौसैनिक गतिविधियों और क्षेत्रीय तनावों के बीच भारतीय नौसेना अपनी क्षमता बढ़ा रही है। खाड़ी क्षेत्र भारत के व्यापार का अहम हिस्सा है, जहां से 60 फीसदी से ज्यादा तेल आयात होता है।

वेनेजुएला में भूकंपः धरती फटी, इमारतें ध्वस्त 1 लाख मौतों की आशंका

कराकस। लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप ने व्यापक पैमाने पर तबाही मचाई है। महज एक मिनट के भीतर आए ताबड़तोड़ दो शक्तिशाली झटकों ने सैकड़ों-हजारों मकानों को जमींदोज कर दिया है। इस प्राकृतिक आपदा में कम से कम 10 हजार से एक लाख तक लोगों के मारे जाने की आशंका जताई गई है, जैसा कि अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपनी प्रारंभिक आकलन रिपोर्ट में चेतावनी दी है। स्थानीय समय के अनुसार, शाम 6 बजे आए भूकंप के इन झटकों ने वेनेजुएला के एक बड़े हिस्से को मलबे में तब्दील कर दिया है। राहत एवं बचावकर्मी युद्धस्तर पर मलबे में दबे लोगों को निकालने में जुटे हैं। वहीं दूसरी तरफ जापान में भी भूकंप के जबरदस्त झटके लगे हैं। आज यानी गुरुवार को जापान की धरती 6.9 तीव्रता के जबरजस्त भूकंप से कांप उठी।

दो दर्जन आफ्टरशॉक्स

वेनेजुएला में स्थानीय समयानुसार शाम 6 बजे दो बेहद शक्तिशाली भूकंपों ने दस्तक दी, जिससे व्यापक तबाही मची। जानकारों के अनुसार, पहला भूकंप 7.2 तीव्रता का था, जिसका केंद्र राजधानी कराकस से करीब 160 किलोमीटर पश्चिम में स्थित था। इसके एक मिनट से भी कम समय बाद 7.5 तीव्रता का दूसरा जोरदार झटका आया, जिसने स्थिति को और भयावह बना दिया। इन दोनों बड़े भूकंपों के बाद लगभग दो दर्जन आफ्टरशॉक्स भी दर्ज किए गए, जिससे पहले से डरे-सहमे लोगों में दहशत और बढ़ गई। शुरूआती तस्वीरों और स्थानीय प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, कई इमारतें ढह गई हैं, बड़ी संख्या में लोग मलबे में फंसे हो सकते हैं और मृतकों की संख्या काफी अधिक होने की आशंका है। भारी जनहानि और व्यापक नुकसान की आशंका जताते हुए कहा है कि यह आपदा बड़े इलाके को प्रभावित करने वाली साबित हो सकती है।

ढहीं इमारतें, फटीं सड़कें रोते बिलखते लोग

भूकंप का मंजर बेहद डरावना है। सड़कें फटीं पड़ी हैं और इमरतें मलबा बन गई। लोग रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। वहीं वेनेजुएला की राष्ट्रीय सरकार ने अभी तक मृतकों और घायलों का आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है। इसके बावजूद, स्थानीय अधिकारियों, चश्मदीदों और टेलीविजन फुटेज से हालात की गंभीरता साफ झलक रही है। भूकंप के झटके शाम करीब 6 बजे महसूस किए गए, जब लोग अपने घरों, दफ्तरों और अपार्टमेंट में मौजूद थे। जैसे-जैसे झटकों की तीव्रता बढ़ी, लोग जान बचाने के लिए घरों और इमारतों से बाहर भागे। राजधानी कराकस सहित कई इलाकों में लोग रात होने के बाद भी सड़कों पर ही डटे रहे, क्योंकि लगातार आफ्टरशॉक्स के बीच घरों में लौटना सुरक्षित नहीं लगा। कराकस के निवासी हेक्टर रिची ने बताया कि शुरूआत में झटके हल्के महसूस हुए, लेकिन धीरे-धीरे उनकी तीव्रता इतनी बढ़ गई कि सभी को घरों से बाहर निकलना पड़ा। एक अन्य स्थानीय निवासी रोबर्टो गामास ने कहा, इमारत एक तरफ से दूसरी तरफ बुरी तरह हिल रही थी। यह अविश्वसनीय था। झटकों की ताकत बेहद ज्यादा थी। हम सड़क पर चल रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो जमीन हमें उछाल रही हो। अपार्टमेंट के भीतर सब कुछ गिर गया। शुक्र है कि हम समय रहते बाहर निकल आए। स्थानीय प्रशासन ने कई इलाकों में इमारतों, मकानों और अन्य ढांचों के ढहने की पुष्टि की है। कई स्थानों पर सड़कें तक फट गईं।

ताजा खबर

संक्षिप्त

बैगा समुदाय के 13 बच्चे बाल श्रम से हुए मुक्त, अब करेंगे पढ़ाई

रायपुर। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले बैगा समुदाय के 13 बच्चे बाल श्रम करने को मजबूर थे। इन बच्चों से पशुपालन फार्मों में मवेशी चराने समेत अन्य काम कराए जा रहे थे। इसकी जानकारी जब छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग को मिली तो विभाग ने सभी बच्चों का रेस्क्यू किया और स्कूलों में दाखिला कराया। दरअसल, मई 2026 में कबीरधाम जिले के भोरमदेव क्षेत्र के थुहापानी गांव और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास स्थित पशुपालन फार्मों में बाल श्रम और मानव तस्करी का मामला सामने आया था। आरोप था कि बैगा समुदाय के 8 से 15 साल के 13 बच्चों को आर्थिक प्रलोभन देकर वहां ले जाया गया था, जहां उनसे मवेशी चराने सहित अन्य काम कराए जा रहे थे। मामले की जानकारी मिलने के बाद संयुक्त कार्रवाई में सभी बच्चों को सुरक्षित मुक्त कराया गया। इस मामले में 2 मानव तस्करों और 6 नियोक्ताओं सहित कुल 8 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। रेस्क्यू के बाद बच्चों के पुनर्वास और शिक्षा पर काम किया गया। विकासखंड शिक्षा अधिकारी बोड़ला की रिपोर्ट के अनुसार सभी 13 बच्चों का दोबारा स्कूलों में प्रवेश सुनिश्चित किया गया है। अब जो बच्चे कुछ समय पहले तक मजदूरी कर रहे थे, वे फिर से किताबों और कक्षाओं की ओर लौट रहे हैं।

मंडल रेल प्रबंधक दयानंद की अध्यक्षता में मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति

रायपुर। मंडल रेल प्रबंधक दयानंद की अध्यक्षता में मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रायपुर की 73वीं बैठक आयोजित की गई । बैठक के दौरान रेलवे बोर्ड द्वारा जारी मानक कार्यसूची के अनुसार जनवरी-मार्च 2026 अवधि की मंडल पर हुई राजभाषा प्रगति की समीक्षा की गई। वरिष्ठ मंडल इजीनियर (समन्वय) उत्कर्ष पाण्डेय ने उपस्थित सभी अधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि,- हम सभी का कर्तव्य है कि वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों का पूर्ण पालन करें। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की यह बैठक हमारे लिए आत्ममूल्यांकन एवं भावी कार्ययोजना निर्धारित करने का एक महत्वपूर्ण मंच है । इस बैठक में हम गत तिमाही के राजभाषा संबंधी आंकड़ों की समीक्षा करेंगे, राजभाषा क्रियान्वयन के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों पर विचार करेंगे। राजभाषा के प्रयोग को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक सुझावों एवं उपायों पर चर्चा करेंगे। मंडल रेल प्रबंधक दयानंद ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि, राजभाषा अधिनियमों व नियमों का पालन करना संवैधानिक विषय है। इसलिए सभी कार्य अनिवार्य रूप से हिन्दी या द्विभाषी होने चाहिए।

पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को मिलेगी नि:शुल्क आवासीय शिक्षा

रायपुर. छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के बेहतर भविष्य निर्माण एवं गुणवत्तापूर्ण नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध करने के उद्देश्य से अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत जिले के श्रेष्ठ आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को कक्षा 6वीं से 12वीं तक गुणवत्तापूर्ण नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों के प्रवेश शुल्क, शैक्षणिक शुल्क, गणवेश, पुस्तक-कॉपी, छात्रावास, भोजन एवं अन्य आवश्यक शैक्षणिक व्यवस्थाओं पर होने वाले समस्त व्यय का वहन मंडल द्वारा किया जाएगा। इस योजना का लाभ पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के उन बच्चों को मिलेगा जिन्होंने कक्षा 5वीं उत्तीर्ण कर ली है। विद्यार्थियों का चयन प्राप्त आवेदनों के आधार पर जिला स्तर पर मेरिट सूची के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। सहायक श्रमायुक्त श्री देवेन्द्र देवांगन ने बताया कि श्रम विभाग द्वारा योजना का लाभ लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 जून से प्रारंभ हो चुकी है तथा 3 जुलाई तक जारी रहेगी। इच्छुक पंजीकृत निर्माण श्रमिक श्रम विभाग की वेबसाइट shramevjayate.cg.gov.in के माध्यम से स्वयं आवेदन कर सकते हैं।

रायपुर की बेटी बनाएगी सैटेलाइट, कलेक्टर ने भेंट कर किया सम्मानित

देशभर से नौ बच्चों का चयन, छत्तीसगढ़ से इकलौती महिमा

रायपुर. स्पेस किड्ज़ इंडिया के प्रतिष्ठित मिशन शक्तिसैट में रायपुर की छात्रा कु. महिमा राजपूत के राष्ट्रीय फाइनलिस्ट के रूप में चयनित होने पर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज उनसे मुलाकात कर शुभकामनाएं दीं। डॉ. सिंह ने महिमा को प्रेरक पुस्तक एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर उज्वल भविष्य की कामना की। शासकीय आदर्श उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय (स्त्रश्वस्), तिलकनगर की प्रतिभाशाली छात्रा कु. महिमा राजपूत का चयन मिशन शक्तिसैट के लिए राष्ट्रीय फाइनलिस्ट के रूप में हुआ है। इस चयन प्रक्रिया के लिए उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था एवं परीक्षा दिया। जिसके पश्चात् उनका चयन हुआ।

यह उपलब्धि विद्यालय, रायपुर जिले एवं छत्तीसगढ़ राज्य के लिए गौरव का विषय है। महिमा ने अपनी प्रतिभा, लगन और वैज्ञानिक सोच के बल पर राष्ट्रीय स्तर पर यह महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। सुश्री महिमा ने कहा कि मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी एवं जिला प्रशासन एवं अपने शिक्षकों एवं प्राचार्य का धन्यवाद करती हूं जिनके मार्गदर्शन एवं सहयोग से आज मैं इस उपलब्धि को हासिल की हूं।

राष्ट्रीय फाइनलिस्ट के रूप में चयनित महिमा राजपूत अगस्त 2026 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाली 8 दिवसीय शक्तिसैट कार्यशाला में भाग लेंगी। यह कार्यशाला अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में छात्राओं को प्रोत्साहित करने तथा उनके वैज्ञानिक कौशल को विकसित करने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगी। इस मिशन में विश्व के 108 देशों की 108 चयनित छात्राएं भाग लेंगी।

23 अगस्त से नई दिल्ली में आयोजित कार्यशाला में छात्राएं मिलकर ShaktiSAT उपग्रह का निर्माण करेंगी। इनमें से एक सैटेलाइट को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जबकि दूसरा चंद्रमा की पर उतरने के उद्देश्य से विकसित किया जाएगा। इन सैटेलाइट्स का प्रक्षेपण अक्टूबर में ढ्ढस्क्रह्र, श्रीहरिकोटा से किया जाएगा। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

शिवरात बोले: जी राम जी योजना ग्रामीण भारत की तकदीर बदलने का अभियान

रायपुर। ग्रामीण परिवारों को आजीविका और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक जुलाई से वीबी-जी-राम जीयोजना लागू होगी। छत्तीसगढ़ के ग्राम पंचायत सांकरा एवं देवरी के ग्रामीणों ने मानव श्रृंखला बनाकर विकसित भारत ङ्क जी राम जी योजना का समर्थन किया, जिसकी सराहना केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। केंद्रीय मंत्री चौहान ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले से आई इस तस्वीर को देखकर मन आनंद और उत्साह से भर गया। यह तस्वीर गांव के जागते हुए आत्मविश्वास का प्रतीक है। जब पूरा गांव हाथ मिलाकर किसी संकल्प के साथ खड़ा हो जाए तो वह जन-आंदोलन बन जाता है। विकसित भारत ङ्क जी राम जी योजना भी ग्रामीण भारत की तकदीर बदलने का अभियान है। ग्राम पंचायत सांकरा एवं देवरी के ग्रामीणों के इस उत्साह को प्रणाम। आइये, 1 जुलाई से शुरू होने जा रही वीबी-जी-राम-जी योजना से जुड़ें और आत्मनिर्भर, विकसित गांव का संकल्प बुनें।

केंद्रीकृत खरीदी व्यवस्था खत्म, राशि सीधे बैंक खातों में होगी जमा

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं-सहायिकाओं को साड़ी के लिए सीधे मिलेंगे 500 रुपये

रायपुर। बीते महीने में साड़ी की क्वालिटी को लेकर किरकिरी झेलने के बाद महिला बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को साड़ी खरीदी की राशि सीधे खातों में देने का फैसला किया है। महिला एवं बाल विकास आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के लिए साड़ी की संचालनालय स्तर पर होने वाली केंद्रीकृत खरीदी व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। अब साड़ी खरीदी के लिए निर्धारित राशि सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में अंतरित की जाएगी। हाल के दिनों में साड़ी खरीदी प्रक्रिया को लेकर सामने आए विभिन्न मुद्दों तथा प्राप्त सुझावों का गंभीरता से परीक्षण करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। यह कदम न केवल व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा बल्कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को अपनी पसंद और आवश्यकता के अनुरूप साड़ी चयन करने की स्वतंत्रता भी प्रदान करेगा। साड़ी का रंग एवं डिज़ाइन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने विभाग को निर्देशित किया है कि साड़ी का डिज़ाइन पूर्ववत रखा जाए तथा अंतिम स्वरूप आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं से परामर्श के बाद निर्धारित किया जाए। साड़ी का रंग एवं डिज़ाइन विभागीय स्तर पर निर्धारित कर उसकी जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि पूरे प्रदेश में एकरूपता बनी रहे। वहीं साड़ी के कपड़े जैसे कॉटन, सिंथेटिक अथवा अन्य विकल्पों का चयन स्थानीय स्तर पर स्वयं कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं कर सकेंगी। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि विभाग में वर्षों से चली आ रही व्यवस्थाओं की भी सतत समीक्षा की जा रही है और जहां भी सुधार की आवश्यकता होगी वहां हितग्राहियों के हित में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे।

डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से राशि का ट्रांसफर

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की स्पष्ट सोच है कि शासन की राशि अधिकतम रूप से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे लक्षित व्यक्ति तक पहुंचे, ताकि बिचौलियों और अनावश्यक प्रक्रियाओं की कोई गुंजाइश न रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने भी प्रदेश में अनेक पारदर्शी और तकनीक आधारित सुधार लागू कर सुशासन का नया मॉडल प्रस्तुत किया है। विभाग का यह निर्णय उसी सोच का विस्तार है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सुशासन की संकल्पना को साकार करने के लिए लगातार बड़े सुधारात्मक कदम उठा रही है। राज्य सरकार अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करते हुए शासन की व्यवस्थाओं को अधिक पारदर्शी, सरल और जनहितैषी बनाने के लिए निरंतर नवाचार कर रही है।

प्रति यूनिफॉर्म अधिकतम 500 रुपये की राशि निर्धारित

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को उनकी पहचान और एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष दो यूनिफॉर्म प्रदान करने का प्रावधान है, जिसके लिए प्रति यूनिफॉर्म अधिकतम 500 रुपये की राशि निर्धारित है।

पद्मश्री से सम्मानित हुईं डॉ. बुधरी ताती

वित्त मंत्री ने कहा- बस्तर की बड़ी दीदी ने बढ़ाया छत्तीसगढ़ का मान

रायपुर. पद्मश्री सम्मान से सम्मानित होने पर दक्षिण बस्तर की समाजसेवी डॉ. बुधरी ताती को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि डॉ. बुधरी ताती ने यह प्रतिष्ठित सम्मान हासिल कर न केवल बस्तर अंचल, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है।

यह सम्मान उनके चार दशक लंबे समर्पित सामाजिक कार्य और आदिवासी समाज के उत्थान के लिए किए गए अथक प्रयासों की पहचान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के हाथों पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वाली डॉ. बुधरी ताती दक्षिण बस्तर के अबूझमाड़ क्षेत्र में लंबे समय से समाजसेवा के कार्यों में सक्रिय हैं। उन्होंने अपना जीवन आदिवासी बच्चियों की शिक्षा, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और बुजुर्गों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। डॉ. बुधरी ताती ने सिलाई प्रशिक्षण, शिक्षा और जागरूकता अभियानों के माध्यम से अब तक 500 से अधिक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान किया है। नक्सल प्रभावित और संसाधनों की कमी वाले क्षेत्र में कठिन परिस्थितियों के बावजूद उनका सेवा कार्य लगातार जारी रहा। स्थानीय लोग उन्हें स्नेह और सम्मान से बड़ी दीदी के नाम से जानते हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि डॉ. बुधरी ताती ने जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार, महिलाओं के सशक्तिकरण और वंचित समुदायों के कल्याण के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया है। उनका जीवन सेवा, समर्पण और सामाजिक परिवर्तन की मिसाल है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में सफल ट्राइबल यूथ हॉस्टल के विद्यार्थियों से की मुलाकात

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में संघ लोक सेवा आयोग (वढरउ) की प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए ट्राइबल यूथ हॉस्टल, द्वारका के विद्यार्थियों से आत्मीय मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह उपलब्धि केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के मेहनतकश परिवारों के सपनों और संघर्ष का सम्मान भी है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इन विद्यार्थियों की सफलता इस बात का सशक्त प्रमाण है कि प्रतिभा कभी भी आर्थिक संसाधनों या पारिवारिक पृष्ठभूमि की मोहताज नहीं होती। किसी के पिता राजमिस्त्री हैं, कोई किसान परिवार से है तो कोई शिक्षक का बेटा है, लेकिन इन सभी ने अपनी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प के बल पर देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा के प्रथम चरण में सफलता प्राप्त की है। यह पूरे प्रदेश, विशेषकर युवाओं के लिए प्रेरणादायी उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से उनकी तैयारी, अध्ययन पद्धति, संघर्ष और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। विद्यार्थियों ने ट्राइबल यूथ हॉस्टल में उपलब्ध अध्ययन वातावरण, मार्गदर्शन और सुविधाओं के अनुभव साझा किए तथा बताया कि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुकूल माहौल ने उन्हें बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें हासिल करने का आत्मविश्वास दिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने विद्यार्थियों से कहा कि प्रारंभिक परीक्षा की सफलता एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन वास्तविक लक्ष्य मुख्य परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना है। उन्होंने विद्यार्थियों को पूरी निष्ठा, अनुशासन, समय प्रबंधन और सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करने की सलाह देते हुए कहा कि कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता और निरंतर प्रयास ही सफलता का सबसे बड़ा आधार है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक सेवाएं केवल एक प्रतिष्ठित करियर नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की सेवा का प्रभावी माध्यम हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से अपेक्षा की कि वे भविष्य में प्रशासनिक दायित्व निभाते समय संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जनसेवा की भावना को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे तथा अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी और बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विशेष रूप से दूरस्थ एवं आदिवासी अंचलों के प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक पहल की जा रही हैं, ताकि प्रतिभा संसाधनों के अभाव में कभी पीछे न रह जाए।

उन्होंने कहा कि द्वारका स्थित ट्राइबल यूथ हॉस्टल इसी सोच का परिणाम है, जहां प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। यहां उपलब्ध शैक्षणिक वातावरण, मार्गदर्शन और आवश्यक सुविधाओं का सकारात्मक परिणाम अब यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में विद्यार्थियों की लगातार बढ़ती सफलता के रूप में सामने आने लगा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का सबसे मजबूत आधार शिक्षित, जागरूक, सक्षम और संवेदनशील युवा हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश का प्रत्येक प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुरूप आगे बढ़े और देश के सर्वोच्च संस्थानों एवं सेवाओं में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करे।

वीरांगना रानी दुर्गावती का शौर्य और बलिदान राष्ट्र की प्रेरणा का अमर स्रोत : मुख्यमंत्री साय

रायपुर. मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित केनाल लिंकिंग रोड पर वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि रानी दुर्गावती का अदम्य साहस, पराक्रम और बलिदान भारतीय इतिहास की अमूल्य धरोहर है। उनका जीवन राष्ट्रप्रेम, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि रानी दुर्गावती का शौर्य और त्याग आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का प्रकाश स्तंभ है। उनकी गौरवगाथा हमें विपरीत परिस्थितियों में भी साहस, आत्मविश्वास और कर्तव्यनिष्ठा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि समाज द्वारा अपने महान नायकों और गौरवशाली इतिहास का स्मरण करना अत्यंत आवश्यक है। जो समाज अपने इतिहास और विरासत को विस्मृत कर देता है, उसका भविष्य भी संकटग्रस्त हो जाता है, जबकि जो समाज अपने महापुरुषों को कृतज्ञता और सम्मान के साथ याद रखता है, उसका भविष्य सदैव उज्ज्वल होता है।ुख्यमंत्री ने रानी दुर्गावती के जीवन प्रसंगों का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने मुगल साम्राज्य की विशाल सेना के सामने अद्वितीय वीरता का परिचय दिया। अंतिम क्षण तक संघर्ष करते हुए उन्होंने मातृभूमि की रक्षा और स्वाभिमान की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी तथा वीरगति को प्राप्त हुईं। उनका बलिदान भारतीय इतिहास में साहस और स्वाभिमान के अप्रतिम अध्याय के रूप में सदैव स्मरणीय रहेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास भी, विरासत भी के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। विकास की यात्रा तभी सार्थक होती है, जब हम अपनी सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक चेतना और महान विभूतियों के योगदान को भी समान रूप से संरक्षित करें। रानी दुर्गावती ने जिस राष्ट्रचेतना, स्वाभिमान और संघर्ष की भावना का संचार किया, वह आज भी समाज को दिशा प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती का जीवन केवल इतिहास का विषय नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है।

मालाबार पाइड हॉर्नबिल के संरक्षण के साथ स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार, पीवीटीजी गांवों में शुरू होगी पहल

उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में शुरू होगी 'हॉर्नबिल सफारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में वन्यजीव संरक्षण और सामुदायिक विकास को नई दिशा देने वाली एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की जा रही है। वन मंत्री केदार कश्यप की पहल पर रिजर्व प्रबंधन द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के गांवों ओढ़, अमलोर और आमामोरा में 'हॉर्नबिल सफारी' प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। यह पहल दुर्लभ मालाबार पाइड हॉर्नबिल के संरक्षण को मजबूती देने के साथ-साथ स्थानीय ग्रामीणों के लिए रोजगार और आय के नए अवसर भी सृजित करेगी। 'हॉर्नबिल सफारी' से तात्पर्य हॉर्नबिल पक्षियों को देखने के लिए की जाने वाली वन्यजीव सफारी या हॉर्नबिल से जुड़े प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों से है। हॉर्नबिल मुख्य रूप से जंगलों, विशेषकर पश्चिमी घाट और मध्य भारत के नम पर्णपाती और सदाबहार वनों में रहना पसंद करता है। हॉर्नबिल संरक्षण के लिए गठित विशेष ट्रैकिंग टीम लगातार पक्षियों की गतिविधियों, घोंसलों और आवास क्षेत्रों की निगरानी कर रही है। वन विभाग के कर्मचारियों के साथ स्थानीय ट्रैकर्स भी इस अभियान से जुड़े हुए हैं। उनके सतत प्रयासों से ओढ़, अमलोर और आमामोरा के आसपास का वन क्षेत्र आज हॉर्नबिल के सुरक्षित आवास और आकर्षक बर्डिंग स्थल के रूप में विकसित हो चुका है। प्रस्तावित हॉर्नबिल सफारी के माध्यम से पर्यटक, पक्षी प्रेमी, वन्यजीव फोटोग्राफर और शोधकर्ता प्राकृतिक वातावरण में हॉर्नबिल का अवलोकन कर सकेंगे। सफारी के संचालन के लिए प्रारंभिक चरण में दो जिप्सी वाहनों की व्यवस्था की गई है। हॉर्नबिल सफारी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता स्थानीय समुदायों की भागीदारी है। पीवीटीजी गांवों के युवाओं और ग्रामीणों को बर्ड वॉचिंग तथा नेचर गाइड का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद वे पर्यटकों के लिए नेचर गाइड और हॉर्नबिल गाइड के रूप में कार्य करेंगे।

संरक्षण और आजीविका साथ-साथ

वन मंत्री केदार कश्यप की सोच के अनुरूप वन विभाग वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण कार्यों को स्थानीय समुदायों की भागीदारी और आजीविका से जोड़ने की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख अरुण कुमार पाण्डेय तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) ओ.पी. यादव के मार्गदर्शन में उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में कई नवाचार किए जा रहे हैं, जिनसे वन्यजीव संरक्षण और ग्रामीण विकास को एक साथ बढ़ावा मिल रहा है।

बढ़ी हॉर्नबिल की आबादी

उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में पिछले चार वर्षों के दौरान मालाबार पाइड हॉर्नबिल की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। यह सफलता एंटी-पोचिंग अभियान, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, फलदार वृक्षों के संरक्षण एवं रोपण तथा 'हॉर्नबिल रेस्टोरेंट' जैसी अभिनव पहल का परिणाम है। स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी ने भी इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

ब्रॉड भी हुए वैभव के मुरीद, बोले उससे संभलकर रहे इंग्लैंड के गेंदबाज

लंदन। इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने 15 साल के उभरते हुए भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा है कि हम उसका खेल देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

वैभव के आक्रामक अंदाज के साथ ही उनकी निडर रवैये से भी ब्रॉड बेहद प्रभावित हैं अनका कहना है कि विरोधी टीम के लिए इस बल्लेबाज पर अंकुश लगाना आसान नहीं होगा। वैभव ने जिस प्रकार से हाल में भारत ए की ओर से खेलते हुए श्रीलंका ह्यएह्न के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी की थी और 11 गेंदों में लिस्ट-ए क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक लगाया था। उससे भी इंग्लैंड के खेमे में जबरदस्त उत्साह है।

ब्रॉड ने कहा, उसके पास सब कुछहै, है न? अब तो वह स्लेजिंग भी करने लगा है! उसके लिए क्रिकेट बहुत आसान हो गया है। 11 गेंदों में अर्धशतक! यह वाकई पागलपन है। उन्होंने आगे कहा, मैं 1 जुलाई को डरहम में भारत के खिलाफ होने वाले पहले टी20 मैच में रहूंगा और मुझे सच में लगता है कि मैं उसे देखकर हैरान रह जाऊंगा। ब्रॉड ने इस बात पर भी जोर दिया कि वैभव की यह चर्चा केवल सोशल मीडिया में बनी हुई कहानी नहीं है। क्रिकेट जगत में हर कोई इसी क्रिकेटरर की बात कर रहा। ब्रॉड ने बताया, मैंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सहायक कोच दिनेश कार्तिक से जबवैभव के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि यह लड़का सचमुच असाधारण है। आप सोच भी नहीं सकते कि यह बच्चा कितना बेहतरीन क्रिकेटर है।

ब्राड के अलावा इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने भी वैभव जमकर प्रशंसा की है।बटलर ने उनके रिकॉर्ड्स की तारीफ करते हुए कहा, उसने भारत ए के लिए 11 गेंदों में 50 रन बनाए, जो लिस्ट-ए इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक है। इंग्लैंड टीम को सावधान करते हुए बटलर ने कहा, यह कुछ ऐसा है जो हमने पहले कभी नहीं देखा। वह जिस तेजी से रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है, वह डराने वाला है। एक इंग्लिश टीम के रूप में हमें टी20 सीरीज में उसपर अंकुश लगाने के तरीके खोजने होंगे। वह वाकई एक अलग स्तर का खिलाड़ी है।

गौरतलब है कि वैभव ने पिछले कुछ महीनों में जिस तेजी से क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान बनाई है, उसने उन्हें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक क्रिकेट का एक चर्चित चेहरा बना दिया है। अब इंग्लैंड दौरे पर सभी की निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि क्या विदेशी पिचों पर भी वैभव उसी रफ्तार से रन बनाएंगे, जिस तरह उन्होंने घरेलू पिचों पर बनाये हैं।

अगले माह के अंत में शुरू हो होगा डीपीएल का तीसरा सत्र

नई दिल्ली। दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) क्रिकेट का तीसरा सत्र 31 जुलाई से शुरू होगा। इसमें ऋषभ पंत, अनुभवी तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा के अलावा नीतीश राणा ,नवदीप सैनी और प्रिंस यादव जैसे खिलाड़ी भाग लेंगे। यह रोमांचक टूनार्मेंट 31 जुलाई से शुरू होकर 30 अगस्त तक चलेगा। इसमें राजधानी की सबसे अच्छी क्रिकेट प्रतिभाएं खेलती दिखेंगी। इससे पहले सभी की नजरें 1 जुलाई को होने वाली खिलाड़ियों की नीलामी पर रहेंगी। इसमें सभी टीमें अपने दल को अंतिम रूप देंगी और नई प्रतिभाओं पर दांव लगाएंगी।

ऋषभ, ईशांत और राणा सहित कई स्टार क्रिकेटर खेलते दिखेंगे

इस लीग ने बहुत कम समय में ही अपनी पहचान बनायी है। इससे अनुभवी खिलाड़ियों के लिए अपने फॉर्म को हासिल करने और युवा और उभरते हुए क्रिकेटरों के लिए अपनी प्रतिभा को बड़े मंच पर प्रदर्शित करने का भी एक अच्छा अवसर रहता है। इसके पिछले सत्र में वेस्ट दिल्ली लायंस ने राणा की कप्तानी में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली बार डीपीएल खिताब जीता था। इस जीत ने न केवल टीम का मनोबल बढ़ा बल्कि लीग में प्रतिस्पर्धा का स्तर भी बढ़ा है। इस बार भी यह देखना होगा कि क्या दिल्ली लायंस टीम अपने खिताब का बचाव कर पाते हैं या नहीं।

पुरुष प्रतियोगिता के अलाव इस लीग के महिला टनार्मेंट में भी रोमांच की कोई कमी नहीं रहने वाली है। देश की कई प्रमुख महिला क्रिकेटर इस मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी, जिनमें स्टार खिलाड़ी श्वेता सहरावत, अनुभवी प्रिया पुनिया, सोनी यादव और आयुषी सोनी जैसे नाम प्रमुख हैं। महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने और युवा प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए यह लीग एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।

भारतीय मूल के जय मूंदड़ा आयरलैंड टी20 टीम में शामिल

जयपुर। भारतीय मूल के जय मूंदड़ा को आयरलैंड ने अपनी टी20 क्रिकेट टीम में शामिल किया है। जय राजस्थान के टोंक जिले से संबंध रखते हैं। अब जय भारत के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज में खेलते दिखेंगे। जय को सीनियर क्रिकेट टीम में पहली बार शामिल किया गया है। यह उनके लिए न सिर्फ एक बड़ा सम्मान है, बल्कि आयरलैंड के लिए खेलने वाले वह भारतीय मूल के दूसरे क्रिकेटर बने जाएंगे। इससे पहले पंजाब में जन्मे सिमी सिंह ने आयरलैंड की ओर से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेला था। किया था, और अब जय मूंदड़ा इसी विशिष्ट सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए तैयार हैं।

जय ने अपने क्रिकेट करियर की शुरूआत राजस्थान के घरेलू मैदानों में एक तेज गेंदबाज के रूप में की थी। हालांकि, समय के साथ उन्होंने अपनी खेल शैली में महत्वपूर्ण बदलाव किए। उन्होंने खुद को एक कुशल बल्लेबाजी ऑलराउंडर के रूप में विकसित किया, जिसकी पहचान न केवल उनकी प्रभावशाली बल्लेबाजी है बल्कि उनकी बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी भी है, जो टीम के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार बन गई। उनकी यही बहुमुखी प्रतिभा और खेल के तीनों आयामों में योगदान देने की क्षमता उन्हें आयरलैंड की राष्ट्रीय टीम तक ले आई है

भारत जैसी एक मजबूत और अनुभवी टीम के खिलाफ टी20 सीरीज में जय मूंदड़ा के पास अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने का एक सुनहरा अवसर होगा।

क्रिकेट किट खरीदने के लिए मां ने अपने गहने तक बेचे थे: क्रांति गौड़

नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकलकर राष्ट्रीय टीम तक पहुंची हैं।

क्रांति का कहना है कि उसके यहां तक पहुंचने में माता-पिता और परिवार ने काफी संघर्ष और त्याग किया था। इसी कारण अब वह उनके लिए खिताब जीतकर गर्व का अनुभव कराना चाहती हैं। क्रांति के अनुसार उसकी क्रिकेट किट खरीदने के लिए उनकी मां ने अपने गहने तक बेच दिए थे। यह उनके परिवार द्वारा किया एक बड़ा त्याग था, जिसने क्रांति को एक गहरी जिम्मेदारी का एहसास कराया। उन्होंने कहा, ह्यपरिवार मेरे लिए इतना कर रहा था, तो मुझे जिम्मेदारी महसूस हुई। मैं उन्हें कुछ लौटाना चाहती थी। मैं उनके बलिदान को मायने देना चाहती थी। क्रांति अपने परिवार की हमेशा आभारी रहेंगी, जिन्होंने उन्हें अपनी पसंद का करियर चुनने और अपने सपनों को पूरा करने की आजादी दी।

उस दौर को याद करते हुए क्रांति बताती हैं, ह्यउस समय कई लड़कियों को घर से बाहर निकलने की भी अनुमति नहीं थी, लेकिन मेरे माता-पिता अलग थे। उन्होंने कभी मुझे यह महसूस नहीं कराया कि मैं कुछ गलत कर रही हूं। उन्होंने मेरे सपने पर भरोसा किया। पैसों की तंगी के बावजूद, उनके माता-पिता ने हर कदम पर उनका साथ दिया। क्रांति मानती हैं कि जब परिवार का साथ हो, तो बाहरी दुनिया की नकारात्मक बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता। उनके परिवार के इस अटूट विश्वास और समर्थन ने उन्हें अपने लक्ष्यों को पाने की ताकत दी।

क्रांति की सफलता ने सिर्फ उनके जीवन को ही नहीं, बल्कि उनके पैतृक गांव घुवारा में भी एक क्रांति ला दी है। उन्होंने गर्व से बताया कि भारत के लिए उनके सफल प्रदर्शनों की वजह से गांव में एक क्रिकेट अकादमी खुल गई है। अब वहां कई लड़कियां क्रिकेट खेलने आ रही हैं और उनके माता-पिता भी उन्हें इस खेल में करियर बनाने की इजाजत दे रहे हैं। क्रांति इन युवा खिलाड़ियों से नियमित रूप से मिलती हैं और उन्हें प्रेरित करती हैं। उनका मानना है कि वर्ल्ड कप जीत ने इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मेक्सिको में छाया फीफा विश्वकप का खुमार

मेक्सिको सिटी। फीफा विश्वकप फुटबॉल के संयुक्त मेजबान मेक्सको में भी लोग खेल के दीवाने हैं पर महंगे टिकटों के कारण कई लोग स्टेडियम जाने में असमर्थ हैं। ऐसे लोग अब सड़कों पर लगी टीवी स्क्रीन पर ही मैच का आनंद ले रहे हैं।

इसी कारण आजकल मेक्सिको सिटी की हलचल भरी गलियों और व्यस्त इलाकों में फुटबॉल प्रशंसक जमे हुए हैं। अब प्लास्टिक की मेजों पर रखे टेलीविजन के सामने जुटी भीड़ पूरे शहर में फैल रही है। खुले मैदानों से लेकर दुकानों तक, टीवी स्क्रीन पर निगाहें टिकाए मेक्सिकोवासी अपनी राष्ट्रीय टीम का जोश बढ़ा रहे हैं। साथ समर्थन कर रहे हैं।

अमेरिका और कनाडा के साथ अपने देश में आयोजित हो रहे इस विश्व कप में मेक्सिको की दो लगातार जीतों ने देश भर में लोगों को उत्साह से भर दिया है। अधिकांश मेक्सिकोवासियों के लिए इन मैचों के महंगे टिकट खरीद पाना संभव नहीं है। ऐसे में, लोगों ने इस भव्य आयोजन से जुड़ने का अपना अनूठा तरीका ढूंढ लिया है : सड़कों पर जश्न मनाना।

गौरतलब है कि फीफा को विश्व कप टिकटों की बढ़ती कीमतों को लेकर दुनिया भर में आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। मेक्सिको में एक औसत कर्मचारी की मासिक आय लगभग 433 डॉलर है, जबकि इस वर्ष की शुरूआत में टिकटों की कीमत 140 डॉलर से 8,680 डॉलर तक थी, जो बाद में बढ़कर फाइनल के लिए लगभग 32,970 डॉलर तक पहुंच गई। एक प्रशंसक का कहना है कि यह सामाजिक असंतोष बढ़ा रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि यह एक ऐसा जश्न है जिसमें हमें बुलाया ही नहीं गया। फीफा अधिकतम कमाई के नजरिये से चल रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोग इससे बाहर हो रहे हैं। हालांकि, फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फैन्टिनो ने इन कीमतों का बचाव करते हुए कहा है कि यह अमेरिकी बाजार के अनुरूप है। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाउम ने भी टिकटों की ऊंची कीमतों की आलोचना करते हुए फीफा से अपनी मूल्य निर्धारण नीति पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है।

टाटा मोटर्स ने की वाहनों की 1 जुलाई से कीमतें बढ़ाने की घोषणा

नई दिल्ली। वाहन निर्मात स्वदेशी कंपनी टाटा मोटर्स 1 जुलाई से अपने कमर्शियल वाहनों की कीमतों में इजाफा करने जा रही है। कंपनी ने इस मूल्य वृद्धि का कारण कमोडिटी मार्केट की लगातार बढ़ती कीमतों और अन्य इनपुट कॉस्ट (उत्पादन लागत) के बढ़ते दबाव को बताया है। यह बढ़ोतरी 2.5 प्रतिशत तक होगी और विभिन्न मॉडलों तथा वेरिएंट्स के आधार पर अलग-अलग लागू होगी। यह चालू वित्त वर्ष में टाटा मोटर्स द्वारा अपने वाणिज्यिक वाहन पोर्टफोलियो में की गई दूसरी मूल्य वृद्धि है, जो बाजार की मौजूदा आर्थिक चुनौतियों को दशार्ती है।इससे पहले, अप्रैल महीने में भी कंपनी ने इसी तरह के कारणों का हवाला देते हुए अपने कॉमर्शियल वाहनों के दाम 1.5प्रतिशत तक बढ़ाए थे।

टाटा मोटर्स भारत में छोटे कॉमर्शियल वाहनों, पिक-अप ट्रकों, इंटरमीडिएट और हैवी कॉमर्शियल वाहनों के साथ-साथ बसों की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्माण और बिक्री करती है, और यह नई दरें उसके पूरे कॉमर्शियल व्हीकल्स पोर्टफोलियो पर प्रभावी होंगी। कंपनी ने मॉडल के हिसाब से कीमतों में बदलाव का खुलासा फिलहाल नहीं किया है। इसी क्रम में, कंपनी ने अपने पैसेंजर व्हीकल्स पोर्टफोलियो की कीमतों में भी 1.5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जो भी 1 जुलाई से ही लागू होगी। पैसेंजर वाहनों की कीमतों में वृद्धि के लिए भी बढ़ती इनपुट कॉस्ट और इन्फ्लेशनरी प्रेशर (महंगाई के दबाव) को मुख्य कारण बताया गया है। यह बढ़ोतरी कंपनी के बेचे जाने वाले इंटरनल कम्बशन इंजन (आईसीई) मॉडल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (ईवी) दोनों पर समान रूप से लागू होगी। यहां इनपुट कॉस्ट का अर्थ किसी भी वाहन के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल जैसे स्टील, एल्युमीनियम, प्लास्टिक और रबर की लागत, मजदूरी और फैक्ट्री के अन्य खर्चों को मिलाकर आने वाली कुल लागत से है।

प्रभु देवा ने खरीदी एमजी एम9 ईवी, कीमत है 75.90 लाख रुपए

नईदिल्ली। मशहूर एक्टर, डांसर और फिल्ममेकर प्रभु देवा अब एमजी एम9 ईवी के मालिक बन गए हैं। एमजी एम9 भारत में बिकने वाली एकमात्र इलेक्ट्रिक लग्जरी वैन है, जो सिंगल चार्ज पर 550 किलोमीटर की प्रभावशाली रेंज देती है और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग (यूरो और ऑस्ट्रेलियन क्रैश टेस्ट में) से लैस है। एमजी मोटर्स की यह सबसे लग्जरी इलेक्ट्रिक एमपीवी, जिसकी कीमत 75.90 लाख रुपए है, प्रभु देवा के गैराज में शामिल हो गई है। सेगमेंट में इसका मुकाबला किआ कार्निवल जैसी गाड़ियों से होता है, लेकिन एमजी एम9 अपने शानदार स्पेस और बेजोड़ कम्फर्ट के लिए जानी जाती है। इस एमपीवी का इंटीरियर लग्जरी और आराम का प्रतीक है, जिसमें कॉग्नेक ब्राउन लेदर का उपयोग किया गया है। फ्रंट में 12.23-इंच की टचस्क्रीन और 7-इंच का ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो और जेबीएल साउंड सिस्टम मिलता है।

भारतीय शेयर बाजार की मजबूती के साथ शुरूआत

सेंसेक्स 400 अंक उछला, निफ्टी 24,100 के पार

मुंबई। पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों का असर गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में साफ दिखाई दिया। शुरूआती कारोबार में प्रमुख सूचकांकों ने जोरदार बढ़त के साथ दस्तक दी। सुबह शुरूआत में निफ्टी 50 सूचकांक 93.25 अंकों की उछाल के साथ 24,114.90 पर कारोबार कर रहा था, जबकि सेंसेक्स 311 अंकों की मजबूती लेकर 77,301.27 के स्तर पर पहुंच गया। प्रमुख शेयरों में रही तेजी तेजी वाले शेयरों की बात करें तो निफ्टी 50 में इंटरग्लोब एविएशन, श्रीराम फाइनेंस और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर शुरूआती कारोबार में सबसे ज्यादा फायदे में रहे।

इन शेयरों ने बाजार को ऊपर ले जाने में अहम भूमिका निभाई। व्यापक बाजार और सेक्टरों का प्रदर्शन व्यापक बाजार में भी निवेशकों का उत्साह देखने को मिला, जहां निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 0.56 फीसदी और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 0.36 फीसदी की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेक्टोरल स्तर पर, निफ्टी ऑटो और निफ्टी रियल्टी सूचकांकों ने शानदार प्रदर्शन किया और हरे निशान में मजबूती से डटे रहे, जबकि निफ्टी मेटल और मीडिया इंडेक्स अपेक्षाकृत कमजोर दिखाई दिए। यह बाजार में चौतरफा खरीदारी का संकेत देता है।

रुपया 31 पैसे मजबूत होकर 94.24 प्रति डॉलर पर खुला

मुंबई। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट से रुपया गुरुवार को शुरूआती कारोबार में 31 पैसे मजबूत होकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94.24 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार, डॉलर की कमजोरी और घरेलू शेयर बाजारों में सकारात्मक रुझान ने भी रुपये को समर्थन दिया। हालांकि, विदेशी पूंजी की भारी निकासी के कारण रुपये की बढ़त सीमित रही। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94.30 पर खुला। फिर मजबूत होकर 94.24 प्रति डॉलर पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव की तुलना में 31 पैसे की बढ़त दशार्ता है। रुपया बुधवार को 21 पैसे मजबूत होकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94.55 पर बंद हुआ था। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दशार्ने वाला डॉलर सूचकांक 0.10 प्रतिशत की गिरावट के साथ 101.50 पर रहा।

सोना 1.40 लाख और चांदी 2.10 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम

सोना इस साल पहली बार 4,000 डॉलर से नीचे, चांदी भी साल के निचले स्तर पर

नई दिल्ली। देशभर सोने की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है। गुरुवार को भी ज्यादातर शहरों में सोना सस्ता हुआ है। 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट वाले सोने की कीमतों में 10 रुपये प्रति 10 ग्राम की मामूली गिरावट दर्ज की गई है।

इससे उन लोगों को राहत मिली है जो शादी-ब्याह या निवेश के लिए सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल सोने के दाम पर दबाव बना हुआ है इसके कारण कीमतों में नरमी देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 1,44,470 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,32,440 रुपये और 18 कैरेट सोना 1,08,390 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। मुंबई और हैदराबाद में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,44,320 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं 22 कैरेट सोना 1,32,290 रुपये और 18 कैरेट सोना 1,08,240 रुपये प्रति 10 ग्राम पर उपलब्ध है।

भाव में तेज नरमी जारी

चेन्नई में सोने के दाम अन्य शहरों की तुलना में अधिक हैं जहां 24 कैरेट सोना 1,45,630 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स पर भी सोने-चांदी के भाव में तेज नरमी जारी है। सोना 4,019 डॉलर प्रति औंस पर खुलने के बाद $21.60 की गिरावट के साथ 3,987.20 डॉलर पर कारोबार कर रहा था, जबकि इसका पिछला बंद भाव 4,008.80 डॉलर था। इसी तरह, चांदी 57.59 डॉलर प्रति औंस पर खुली और 1.40 डॉलर की गिरावट के साथ $56.68 पर आ गई, जो इसके 58.08 डॉलर के पिछले बंद भाव से नीचे है। दोनों कीमती धातुएं इस साल दर्ज किए गए अपने उच्चतम स्तरों से काफी लुढ़क चुकी हैं।

महत्वपूर्ण ख़बर

मुख्यमंत्री ने कैप्टन मनोज कुमार पांडेय की जयंती पर किया नमन

■ भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन मनोज कुमार पांडेय की जयंती पर उन्हें सादर नमन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा कि कैप्टन पांडेय ने अद्वितीय पराक्रम से कारगिल युद्ध में शत्रु सेना से खालूबार मोर्चे को बचाते हुए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। साहस और पराक्रम से भरा कैप्टन पांडेय का जीवन युवाओं को देश की सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लोकतंत्र प्रहरियों को किया नमन

■ भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आपातकाल की विभीषिका के विरूद्ध डटकर खड़े होने वाले लोकतंत्र प्रहरियों को नमन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा कि 25 जून, 1975 देश में लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन था। आज के दिन ही 1975 में इंदिरा सरकार के अहंकार के परिणामस्वरूप देश में आपातकाल लगाया गया था। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए सदैव समर्पित होकर देश की सेवा का संकल्प लेने का प्रदेशवासियों से आव्हान किया।

अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 27 जून को

■ भोपाल। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 2026 पर 'सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्यप्रदेश समिट' शनिवार 27 जून को रविन्द्र भवन, भोपाल में आयोजित होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा किया जा रहा है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री चेतन्य कुमार काश्यप और मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन समिट में विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।

उद्योग आयुक्त श्री दिलीप कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव भूमि आवंटन, भूमिपूजन, लोकार्पण तथा एमएसएमई, स्टार्टअप एवं स्वरोजगार लाभार्थियों को चेक प्रदान करेंगे। समिट में खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र एवं परिधान तथा अभियांत्रिकी क्षेत्रों के एमएसएमई के लिए बायर-सेलर मीट आयोजित होगी।

पुलिस प्रशिक्षण शालाभौंरी में 572 नव आरक्षकों के बुनियादी प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ

■ भोपाल। मध्यप्रदेश पुलिस पेशेवर, संवेदनशील एवं जनोन्मुखी पुलिसिंग को सुदृढ़ करने के लिए अपने मानव संसाधनों के क्षमता विकास पर निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी परिसर स्थित पुलिस प्रशिक्षण शाला (पीटीएस), भौंरी, भोपाल में 23 जून को5वें नव आरक्षक बैच के 572 नव आरक्षकों के बुनियादी प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ पुलिस उप महानिरीक्षक (ग्रामीण), भोपाल श्री राजेश सिंह चंदेल के मुख्य आतिथ्य मेंहुआ। इस बैच में 449 महिला एवं 123 पुरुष नव आरक्षक शामिल हैं, जो पुलिस बल में महिलाओं की बढ़ती सहभागिता और सशक्त उपस्थिति को भी रेखांकित करता है।

सायबर अपराध में सावधानी ही है सबसे बड़ा बचाव

सायबर सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने की जरूरत, हर नागरिक बने डिजिटली जागरूक: मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सायबर खतरा एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है , जो बिना दस्तक दिए हमारे घरों तक पहुंच रहा है। सायबर खतरों को समझना ही उनसे बचने का सबसे बड़ा रास्ता है। सावधानी ही सुरक्षा है और जानकारी ही बचाव है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट, डीप-फेक, फेक प्रोफाइल, हैकिंग, डेटा ब्रीचिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, ओटीपी धोखाधड़ी, ऑनलाइन शॉपिंग ठगी, रैनसमवेयर हमले और फर्जी निवेश लिंक जैसे अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रत्येक नागरिक को सतर्क रहने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश की जनता को सायबर सुरक्षा के तीन महत्वपूर्ण सूत्र 'जागरूकता, सावधानी और सहभागिता' के बारे में बताकर कहा कि जो लोग सायबर सुरक्षा की जानकारी रखते हैं, वे दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को रवीन्द्र भवन में आयोजित ह्यराज्य व्यापी सायबर जागरूकता अभियानन्न के तहत ₹सेफ क्लिक 2.0" के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। यह अभियान 24 जून से शुरू होकर 8 जुलाई तक प्रदेश के 10 संभाग, 55 जिलों और 50 हजार से अधिक गांव में एक साथ चलेगा। इस अभियान के तहत सायबर ठगी और अन्य अपराधों से बचने के लिए जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सायबर जागरूकता अभियान के पोस्टर, स्कूली बच्चों के लिए तैयार की गई सायबर जागरूकता बुकलेट्स तथा अभियान के ऑफिशियल वीडियो का विमोचन किया। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सायबर जागरूकता रथ को झंडी दिखाकर

रवाना किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को तुलसी का पौधा भेंट कर स्वागत किया गया। समापन पर प्रतीक चिन्ह प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अभियान के संचालन के लिए मध्यप्रदेश पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि संकट के समय मध्यप्रदेश पुलिस हमेशा संकटमोचक हनुमान की भूमिका में रहती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि वर्ष 2025 में प्रदेश में विभिन्न सायबर जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से 33 लाख से अधिक नागरिकों को जागरूक किया गया। अब अभियान का विस्तार पंचायतों, स्कूलों, बैंकों, बाजारों, धार्मिक स्थलों और सरकारी कार्यालयों तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार के 56 विभागों की लगभग 1700 सेवाएं एकीकृत पोर्टल पर उपलब्ध हैं और इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेशवासियों से सायबर सुरक्षा को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान करते हुए कहा कि वर्तमान दौर में सायबर खतरे अदृश्य रूप में हमारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन और कंप्यूटर के माध्यम से होने वाले सायबर अपराधों से बचाव के लिए सावधानी और जागरूकता ही सबसे प्रभावी हथियार है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सायबर अपराधों के प्रति प्रदेशवासियों को जागरुक करने के लिए मध्यप्रदेश पुलिस का ₹सेफ क्लिक 2.0" सायबर जागरूकता अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अभियान से प्रदेश के सभी नागरिक जागरूक होंगे। उन्होंने कहा कि सायबर अपराधी एक प्रकार से डिजिटल दौर के राक्षस हैं, जो दबे पाँव लैपटॉप, कम्प्यूटर और मोबाइल के जरिए हमारे साथ सेंधमारी और डकैती करते हैं। आजकल डिजिटल अरेस्ट, डीप फेक, डेटा ब्रीजिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, रेनसमवेयर अटैक जैसे अनेक प्रकार के सायबर अपराध संचालित हैं। लेकिन सायबर अपराधों के मामले में सावधानी ही बचाव है। मध्यप्रदेश पुलिस ने देश में पहली बार सायबर डकैती का लाइव पदार्फाश किया था। इसके लिए मध्यप्रदेश पुलिस बधाई की पात्र है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश पुलिस ने पिछले वर्ष अपने सायबर जागरुकता अभियान के माध्यम से लगभग 33 लाख से अधिक नागरिकों को सतर्क किया था। इस वर्ष 15 दिन तक चलने वाले ₹सेफ क्लिक 2.0" अभियान में हर दिन अलग थीम रखी गई है। इस दौरान लोगों को बैंकिंग, महिला सुरक्षा, ग्रामीण इलाकों में जागरुकता के बारे में बताया। यह अभियान बैंकों, बाजारों, स्कूलों, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थलों पर संचालित किया जाएगा। इसके लिए लोकरंजन के रुचिकर कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। सायबर सुरक्षा को जागरूकता, सावधानी और सहभागिता के माध्यम से प्रभावी बनाया जाएगा। सायबर अपराध हेल्पलाइन 1930 और नेशनल सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। यह नंबर सायबर अपराध के मामले में सबसे पहले पीड़ितों की ढ़ाल बनता है।

लालच और जल्दबाजी कर सकती है आर्थिक नुकसान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नागरिकों को सचेत करते हुए कहा कि अगर आपको कोई अनजान लिंक मिले या डराने धमकाने की कॉल आए तो ₹रुको, सोचो और फिर एक्शन लो"। लालच और जल्दबाजी आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है। पुलिस के अभियान को जन जागरुकता अभियान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हम सभी सहभागी बनें। राज्य सरकार ने सायबर अपराध के विरुद्ध मजबूत फ्रेमवर्क तैयार किया है। नागरिकों के डेटा संरक्षण के लिए डिजिटल पर्सनल डेटा एक्ट को भारत सरकार ने लागू किया है। प्रदेश में कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम का गठन किया गया है। राज्य शासन के 56 विभागों की 1700 से अधिक सेवाओं को एक पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है। यह एक प्रशंसनीय पहल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ₹सेफ क्लिक 2.0" अभियान में बैकों, बाजारों, धार्मिक स्थलों सबको जोड़ा गया है। अभियान को शुरू करने का यही सही समय है, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालयों में प्रवेश ले रही है।

जागरुकता ही सायबर क्राइम से बचने का है सुरक्षा कवच : डीजीपी श्री मकवाना

पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना ने कहा कि मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा 24 जून से 8 जुलाई तक सेफ क्लिक 2.0 सायबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज सायबर अपराध केवल एक आर्थिक चुनौती नहीं है, बल्कि यह समाजिक विश्वास और राष्ट्रीय सुरक्षा के भी जुड़ा गंभीर विषय है। पिछले कुछ वर्षों में सायबर अपराधों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और करीब 80 प्रतिशत शिकायतें वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित होती हैं। डिजिटल अरेस्ट, डीपफेक, फर्जी प्रोफाइल, फर्जी सिमकार्ड, म्यूल बैंक अकाउंट, महिला एवं बच्चों के जुड़े अपराधों की संख्या भी बढ़ी है। मध्यप्रदेश पुलिस सायबर अपराध पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है- रोकथाम, अनुसंधान और जागरुकता। इसी दिशा में 25 दिसंबर 2025 से प्रदेश में ई-जीरो एफआईआर की शुरूआत की गई है। वर्तमान में 1 लाख रुपए तक की सायबर धोखाधड़ी की ई-जीरो एफआईआर दर्ज कर पीड़ितों को न्याय दिलाया जा रहा है। इसके साथ ही हेल्पलाइन नम्बर 1930 से पीड़ितों को त्वरित सहायता भी उपलब्ध हो रही है। सायबर धोखाधड़ी से संबंधित राशि को बैंक खाते में रोकने और अकाउंट होल्डर को दिलवाने में प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2025 में कुल 135 करोड़ राशि होल्ड कराई गई। पीड़ितों को भी राशि दिलवाई गई। पुलिस सायबर अपराध से जुड़े सिस्टम को चिन्हित कर ठोस कार्रवाई कर रही है। म्यूल अकाउंट्स और सायबर स्लेवरी से जुड़े लोगों की पहचान भी की जा रही है।

सायबर अपराध रोकने चलाये जा रहे हैं विशेष अभियान

मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा विशेष अभियान ऑपरेशन फास्ट", ऑपरेशन फेस्ट", ऑपरेशन मैट्रिक्स", ऑपरेशन नयन" संचालित किए गए। मध्यप्रदेश पुलिस को डीएससीआई अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है।

सायबर अपराधों की रोकथाम और जन जागरुकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। मप्र पुलिस ने करोड़ों लोगों को अपने जागरुकता अभियान से जोड़ा है। पहला ₹सेफ क्लिक" अभियान जन जागरुकता का विषय बना था। इससे डिजिटल अरेस्ट पर बहुत हद तक रोक भी लगी थी। उन्होंने कहा कि ₹सेफ क्लिक 2.0" अभियान से इन प्रयासों को और ज्यादा गति मिलेगी, इस अभियान का मूल मंत्र है। सावधानी ही बचाव है।

अदम्य साहस, अद्वितीय पराक्रम और साहस की मिसाल थीं वीरांगना रानी दुर्गावती : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

जबलपुर एयरपोर्ट का नाम होगा रानी दुर्गावती के नाम पर

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि रानी दुर्गावती, अदम्य साहस, अद्वितीय पराक्रम और साहस की प्रतिमूर्ति थीं। नारी शक्ति का पराक्रम मां दुर्गावती के व्यक्तित्व में नजर आता है। मुगलों को युद्धों में धूल चटाने वाली ऐसी वीरांगना रानी दुर्गावती का आज 463वां बलिदान दिवस है। रानी दुर्गावती ने गौंडवाना साम्राज्य में 52 गढ़ों पर शासन किया। पति की असमय मृत्यु के बाद 5 साल के बेटे को सिंहासन पर बैठाया और 15 साल तक जनता की सेवा के लिए और क्षेत्र की रक्षा के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। मध्यप्रदेश की धरती पर लगभग 500 वर्ष पूर्व रानी दुर्गावती का जन्म हुआ, लेकिन आज पूरा देश और प्रदेश उन्हें आदर के साथ स्मरण करता है। हमारा सौभाग्य है कि प्रदेश सरकार के गठन के बाद मंत्रि-परिषद की पहली बैठक जबलपुर में रानी दुर्गावती को समर्पित कर आयोजित की गई थी। इसके बाद दूसरी कैबिनेट बैठक रानी दुर्गावती के गौंडवाना साम्राज्य की राजधानी संग्रामपुर में आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि जबलपुर एयरपोर्ट का नाम वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर रखने के लिए केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस

पर उनकी समाधि स्थल नर्रई नाला जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रानी दुर्गावती को समर्पित नवीन संस्थान जबलपुर में 100 करोड़ रूपए की लागत से मदन महल के पास तैयार हो रहा है, जिसका लोकार्पण बहुत जल्द किया जाएगा। इस संस्थान से प्रदेश की भावी पीढ़ी रानी दुर्गावती के गौरवशाली अतीत और कार्यों से परिचित होंगी। जबलपुर में रानी दुर्गावती के नाम पर एक चिड़ियाघर (ज़ू) और वन्य प्राणी रेस्क्यू सेंटर बन रहा है। इसके साथ ही 35वीं बटालियन मंडला का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर रखा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के नायकों की वीरता और समृद्ध विरासत को सही रूप में प्रस्तुत करने के लिए 'विरासत से विकास' अभियान शुरू किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रानी दुर्गावती का शासन काल, गौंड साम्राज्य का स्वर्णिम युग था। रानी दुर्गावती ने किसान कल्याण के लिए उस दौर में बीज संग्रह, फसल चक्रण और जल संचय के महत्वपूर्ण कार्य कराए थे। उनके प्रबंधन के परिणाम स्वरूप अनाज के भंडार भरे हुए थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए संकल्पित है और पूरा वर्ष किसानों को समर्पित करते हुए ठोस निर्णय ले रही है। अब किसान बंधुओं के लिए शून्य ब्याज दर पर 31 मार्च तक कर्ज चुकाने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। किसान जिस तारीख को लोन लेंगे, तब से एक वर्ष की समयावधि में कर्ज चुकाया जा सकेगा। राज्य सरकार 880 करोड़ रुपए का भुगतान वित्तीय संस्थाओं को करेंगी। राज्य सरकार पर्यटन, उद्योगों और अधोसंरचना विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। शासकीय परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करने पर सरकार किसानों को अब चार गुना मुआवजा देगी। प्रदेश में संचालित रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना से कोदो-कुटकी पैदा करने वाले किसानों को लाभ मिल रहा है। प्रदेश की लाड़ली बहनों को हर माह जारी हो रहे 1500 रुपए से उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ी है। किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि का भी लाभ मिल रहा है। रानी दुर्गावती द्वारा किसानों के कल्याण के लिये चलाये गये कार्यक्रमों से प्रेरित होकर प्रदेश सरकार भी निरंतर कृषक हित में कार्य कर रही है। हमारी सरकार के पास किसान कल्याण और कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की कमी नहीं है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जनजातीय कल्याण के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी लगातार कार्य कर रहे हैं। देश में पहली बार जनजातीय वर्ग श्रीमती द्रौपदी मुर्मु राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रही हैं। राज्य सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के भाव से काम कर रही है। हमारी सरकार जो कहती है, वो करके दिखाती है।

गुणवत्ता की निगरानी के मानक मापदंड किए जाए निर्धारित : राज्यपाल

भोपाल। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि योजनाओं की मंशा और क्रियान्वयन की व्यवहारिकता में संवेदनशीलता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का मूल्यांकन मुख्यतः तकनीकी विषय है, इसलिए हितग्राहियों की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।

निर्माण सामग्री एवं कार्य की गुणवत्ता की निगरानी के मानक मापदंड निर्धारित किए जाए। अधिकारियों द्वारा निगरानी मापदंड के अनुसार नियमित गुणवत्ता परीक्षण करना चाहिए।

राज्यपाल श्री पटेल लोक भवन में बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल को बैठक में पीएम-जनमन योजना अंतर्गत 9 विभागों की 11 अधोसंरचनात्मक, 7 हितग्राही मूलक योजनाओं और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 17 विभागों की 25 योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी गई। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि जनजातीय बहुल क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता की पहल पीएम-जनमन योजना और धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजनाएं है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य के लिए निर्धारित समय सीमा तक कार्य की रीति-नीति उचित नहीं है। रणनीति, समय सीमा से पहले कार्य पूरा करने की होनी चाहिए। नए कार्यों के क्रियान्वयन में पूर्व अनुभवों और चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुए कार्य योजना तैयार की जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अति पिछड़ी जनजातियों के विकास और उत्थान के प्रयासों को आवश्यकता और बहुलता की प्राथमिकता के साथ क्रियान्वयन की औपचारिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए।

राज्यपाल श्री पटेल ने प्रदेश में सिकल सेल उन्मूलन अभियान के तीव्र गति से क्रियान्वयन पर हर्ष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 से पूर्व वर्ष 2026 तक लक्ष्य का पूरा होना अनुमानित है। उन्होंने सभी संबंधितों को इसके लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि 15 वर्ष की आयु तक के सिकल सेल रोगी वाहक के स्वास्थ्य प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे उनका भावी जीवन सुरक्षित हो जाएगा। जरूरी है कि सिकल सेल की दवाओं की उपलब्धता सदैव सुनिश्चित रहे। एलोपैथिक उपचार पद्धति के साथ ही आयुर्वेद औषधियों के उपयोग के संबंध में जन जागरण के प्रयासों की जरूरत भी बताई। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद की दवाओं के उपयोग से रक्त की उपलब्धता बढ़ने और थकान में कमी के उत्साह जनक प्रारंभिक परिणाम प्राप्त हुए है। राज्यपाल ने बैठक में जनजातीय बहुल क्षेत्रों की तहसीलवार बुनियादी सुविधाओं का मानचित्र तैयार कर प्रभावी निगरानी, जन औषधि केन्द्रों के संचालन में जनजातीय युवाओं की भागीदारी तथा विद्यालयों में छात्राओं, छात्र के पृथक शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर बल दिया।

दुधारू पशुओं की वितरण पद्धति का आधार अति-गरीब को प्राथमिकता हो: राज्यपाल

दुग्ध संग्रहण एवं विपणन की व्यवस्था को मजबूत करें : पशुपालन एवं डेयरी विभाग समीक्षा बैठक सम्पन्न

भोपाल। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना के हितग्राहियों को दुग्ध संग्रहण एवं विपणन की मजबूत व्यवस्था उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाए। उन्होंने कहा कि हितग्राही को उत्पादित दुग्ध का उचित मूल्य दिलाने के लिए परिवहन व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए। विभागीय अथवा थर्ड पार्टी समन्वय से आवश्यक वाहनों की उपलब्धता पर विचार किया जाए।

राज्यपाल श्री पटेल बुधवार को लोक भवन में आयोजित पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। बैठक में प्रदाय पशुओं के स्वास्थ्य, देखभाल एवं मॉनिटरिंग व्यवस्थाओं, हितग्राहियों को पशुपालन प्रशिक्षण, वनाधिकार पट्टा धारकों को लाभान्वित करने और हितग्राही अंशदान के संबंध जानकारी दी गई। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा है कि मुख्यमंत्री दुधारू पशु योजना अति-गरीब के पोषण और सतत आजीविका की पहल है। योजना की सफलता के लिए अति-गरीब को प्राथमिकता वितरण पद्धति का आधार होना चाहिए। उन्होंने अति-पिछड़ी जनजातियों बैगा, भारिया और सहरिया के अति-गरीब को प्राथमिकता से लाभान्वित करने के प्रयासों पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आबादी के अनुपात में वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। योजना की जानकारी के लिये अति-पिछड़ी जनजातियों के बीच प्रचार-प्रसार किया जाए। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि पशु वितरण कार्यक्रम में लाभान्वित महिला हितग्राहियों के माध्यम से पशुपालन व्यवस्थाओं और परिवार की आय में बढ़ोतरी के संबंध में जानकारी प्रदान करने की पहल करें। योजना की उपलब्धियों का वर्षवार चित्रात्मक विवरण संधारित

किया जाए।

राज्यपाल श्री पटेल ने गुजरात राज्य में जनजातीय बहुल क्षेत्र में दुग्ध संजीवनी योजना के अनुभवों का उल्लेख करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पशु प्रदाय योजना के हितग्राहियों को परिवार के बच्चों के लिए दुग्ध की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की समझाइश दी जाए। विभाग के द्वारा 2 महिला, 2 पुरुष अधिकारियों को बनासकांठा के डेयरी उद्योग का अध्ययन करने के लिए गुजरात राज्य भेजने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल श्री पटेल को प्रमुख सचिव पशुपालन एवं डेयरी श्री उमाकांत उमराव ने बताया कि प्रदेश के किसानों, पशुपालकों को मोबाइल पर ही पशुओं के पोषण संबंधी जानकारी दी जा रही है। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से पशुओं को आहार मिले, इसके लिए विभाग द्वारा गोरस मोबाइल ऐप तैयार कराया गया है। यह ऐप पूरी तरह से सरल हिंदी भाषा में विकसित किया है। इसके लिए नेट की भी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में ब्रीडर एसोसिएशन का विकास किया जा रहा है। इसमें एक ही नस्ल के 20 से अधिक पशुओं के प्रमाणीकरण के द्वारा उन्नत नस्ल के पशुओं की राज्य में ही आपूर्ति के प्रयास किए गए हैं। उन्होंने बताया कि योजना क्रियान्वयन के लिए 5 वर्षों के प्रावधान और बजट वृद्धि की गई है। प्रति इकाई पशु कीमत को भी बढ़ाया गया है। बीमा की भी व्यवस्थाएं की गई है। कार्य क्षेत्र 12 से बढ़ाकर 24 जिलों में किए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। उमरिया जिले के समस्त हितग्राहियों को 2 पशु प्रदान करने की उपलब्धि हासिल की गई है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा योजना अंतर्गत 100 लीटर दुग्ध संकलन क्षेत्रवार दुग्ध सहकारी संस्थाएं बनाई जा रही हैं। इन समितियों के सचिव के रूप में हितग्राहियों को अतिरिक्त आय भी उपलब्ध होगी। उन्होंने प्रदाय पशुओं के स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में बताया कि वितरण पश्चात तीन माह तक पुनः आकलन कर हितग्राहीवार समीक्षा की जा रही है। पशु चिकित्सक द्वारा साप्ताहिक भ्रमण कर आवश्यक उपचार, टीकाकरण एवं डीवर्मिंग कराई जा रही है।

संपादकः अली आदिल खान द्वारा सांई प्रिंटिंग प्रेस डी-85, न्यू अशोक अगर, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, यूपी से मुद्रित कराकर सी-148, साउथ मोती वाग,पो. चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021 से प्रकाशित किया।
RNI No.: DELMUL/2012/47011 | Email:timesofpedia@gmail.com | समाचार चयन एवं प्रकाशन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार तथा समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।